साप्ताहिक

पृथ्वी पर हम सब समय माया के यात्री हैं

# समय माया

R.N.I. No.: MP/HIN/2006/20685

प्रधान संपादक- अजमेरा एस.पी. कुमार
B.COM., M.A., LLB, CAIIB, DLLLW&PM

Webite: www.samaymaya.com
Email: samaymaya@gmail.com
samaymaya@rediff.com

Cell: +91 9425125569
+91 9479535569

(C) All Copyrights reserved with chief editor, do not publish any matter without prior written permission

In case of any dispute, may be solved only in Indore Court Jurisdiction

वर्ष 17 | अंक 46 | प्रति सोमवार इंदौर, 17 जून से 23 जून 2024 | पृष्ठ 8 | मूल्य 5/- रुपए

## अमेरिकी संचार तंत्र के षड्यंत्रकारी मकड़जाल में विश्व की हर राष्ट्र व सरकारें

# विश्व के हर वर्ग की जनता, व्यवसाय, उद्योग, धंधे, धर्म, सरकारें गुलाम

**रूस, चीन अमेरिकी इंटरनेट का उपयोग नहीं करते उनका सब कुछ अपना, भारत में सरकारी डकैतों को बहुराष्ट्रीय कंपनियों से मोटा कमीशन मिलता है कोई व्यवस्था नहीं।**

अमेरिका के संचार तंत्र के मकड़ जाल ने जिसे आधुनिक विज्ञान की प्रगति बोला जाता है यथार्थ में उसने पूरी दुनिया को उस मकड़ जाल में ऊलझाकर गुलाम बना कीमती समय बर्बाद करने के साथ में उसको मानसिक रूप से सोने की क्षमताएं खत्म कर शारीरिक रूप से इन उपकरणों को हाथ में था में रहकर आपकी शारीरिक क्रियाओं को बंद कर भी अपंग बना रहा है। यह षड्यंत्र व्यक्तिगत मानव जीवन से लेकर परिवार समाज और राष्ट्र और राष्ट्र के साथ राष्ट्रों की सभी सरकारी यथार्थ मेंअमेरिकी संचार तंत्र की मकड़ जाल में उलझा कर उसका हर तरह से व्यावसायिक उपयोग किया जा रहा है।

व्यक्तिगत जीवन से लेकर सार्वजनिक जीवन और सरकारों तक की सारी बातचीत लेन देन आवश्यकताओं कार्यों आदि की गोपनीययता को चीन, अमेरिका के साथ दुनिया की हर सरकारी कंप्यूटर मोबाइल पर चल रहे इंटरनेट के मकड़ जाल के माध्यम से ईमेल, सर पत्राचार, सभाएं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जो कि गूगल के विभिन्न एप्स के माध्यम से संग्रहित कर सबको खोखला बना चुकी है। कहीं कोई शयन कक्ष से लेकर सैन्य स्तर तक गोपनीयता नहीं बची। लगातार पिछले 18 साल से लिखने के बाद में भी कि भारत सरकार सबसे पहले अपना डाटा संग्रहण केंद्र के साथ-साथसारे डेटा को जो करोड़ों गीगाबाइट में होता है। अभी तक अपने यहां संग्रहित करने रोकने और सार्वजनिक होने से बचने के लिए कोई प्रयास यूपीटीईटी नहीं कर रही उल्टे ही वह जनता को आधार कार्ड जबकि आज आधार कार्ड के माध्यम से पूरे देश की 125 करोड़ जनता को बंधक बनाने के साथ उसकी सारी गोपनीयता को भी अमेरिका चीन जापान के साथ अन्य देशों को नीलाम कर रहा है। उल्टे ही बहुराष्ट्रीय कंपनियों से मोटा कमीशन खाकर मोदी उसकी नीति आयोग संचार माध्यम व पूरे मंत्रालय बच्चों के आधार कार्ड से लेकर उनके स्कूल एडमिशन आदि तक को उससे जोड़ चुकी है। दूसरी तरफ आधार कार्ड से सरकार ने जनता को विवश कर, दंड ठोकने, उसका पैन कार्ड, वाहन, मोबाइल, बैंक खाते, सारी संपत्तियों के दस्तावेज के साथ-साथ उसके एटीएम पेटीएम ऑनलाइन भुगतान आदि को जोड़ने उसके हर लेनदेन पर निगाह रखने का जो षड्यंत्र कर रही है यथार्थ में वह जनता के साथ उसकी मौत का सामान भी बन रहा है। क्योंकि बहुराष्ट्रीय कंपनियां उनके विश्लेषक और वर्तमान में अंकीय समंक विश्लेषण या डिजिटल डाटा एनालिसिस एक बहुत बड़ा व्यवसाय बन कर हर उम्र की व जनता के हर वर्ग की खाने-पीने उठने बैठने सांस लेने शरीर में कौन-कौन से रोग हैं क्या-क्या आवश्यकतायें हैं धन कहां से आता है? कहां जाता है? आदि तक का अध्ययन कर अपने व्यवसाय में दुरुपयोग कर रही है के विपरीत हैकर्स अब धनाढ्य लोगों को आपके ही घर में इंटरनेट अरेस्ट करके ठगी लोटो दशक के साथमौत का व्यवसाय भी करने लगे हैं। इस कांड में गेमिंग कंपनी भी पीछे नहीं। वे बच्चों को लालच देकरन केवल जाती हैं। बैंक खाता खाली करती हैं और अंत में उनको आत्महत्या करने तक के लिए बेहोश कर देती हैं तो आखिर यह पूरी दुनिया में अमेरिकी सूचना तंत्र का मकड़ जाल किस प्रकार से दुनिया की जनता की हर उम्र के हर वर्ग के लोगों को कैसे आधुनिक तरीके से शारीरिक मानसिक और आर्थिक रूप से गुलाम बनाने का षड्यंत्र कर रहा है इसे तत्काल रोका जाना चाहिए।

### क्या हम डिजिटल गुलाम हैं? ऑनलाइन 'गोपनीयता' क्यों एक ग़लत नाम

ऑनलाइन व्यक्तिगत डेटा के दुरुपयोग को गोपनीयता का 'मुद्दा' कहना कुछ अजीब है। जब हम कपड़े उतारते हैं या अपने प्रियजनों से बात करते हैं तो हमें 'गोपनीयता' की आवश्यकता होती है; यह शर्म और शर्मिंदगी जैसी भावनाओं के बारे में है। डिजिटल दुनिया में हम बहुत सी चीजों को 'गोपनीयता का मुद्दा' कहते हैं; लेकिन क्या मेरे क्रेडिट कार्ड की जानकारी चुराना और उसका इस्तेमाल कर कर्ज लेना वाकई गोपनीयता का मुद्दा है? क्या यह वाकई मेरी कार की चाबी चुराकर भाग जाने जैसा नहीं है? क्या हम कार चोरी को 'गोपनीयता का उल्लंघन' कहेंगे?

(शेष पेज 2 पर)

## 56 इंची चुप हो देख रहा देश की सीमाओं में अतिक्रमण

# चीन को लाल आंख तो दूर, नेपाल हड़प रहा देश की भूमि

### देश की सीमाओं की रक्षा भाड़ में रंगा बिल्ला देश की लूट में मस्त

भारत की सत्ता को छल बल, दल से कब्जा जमा कर पिछले 10 सालों से केवल मोदी और अमित शाह देश को लूटने में लगे हुए हैं। बेशक देश की रक्षा व्यवस्थाओं के नाम पर लगभग 30 लाख करोड रुपए से ज्यादा का कबाड़ा पिछले 10 सालों में मोदी ने विदेशों में अपने स्वागत सत्कार व झांकी जमाने के लिए अमेरिका फ्रांस रूस ब्रिटेन इजरायल आदि से समय बाधित उपयोग किए हुए कबाड़ा तमंचे पिस्टल से लेकर बंदूकें मिसाइल राडार विमान पनडुब्बियां आदि तक पाठ से 25 गुना कमीशन पर खरीदे। दूसरी तरफ रक्षा बजट को कम करने वहां पर मोटा पैसा कमीशन में हर कदम पर हजम करने एक तरफ 40 लाख की सैनिकों की संख्या धीरे धीरे घटाकर 30, 25, 20, 15 और अब 10 लाख पर

लाकर टिका दी जहां 40 दिन का गोला बारूद रखा जाता थावह भी 10 दिन का गोला बारूद रखा जाने लगा। उत्तर से उत्तर पूर्वीभारत की सीमा लगभग 40 किलोमीटर से ज्यादा चीन से लगती है और वह लगातार अतिक्रमण कर कई स्थानों पर 100 किलोमीटर अंदर घुसकर उसने कालोनियां बनाकर सड़के रेलवे लाइन हवाई अड्डे आदि बना लिएपरंतु मोदी सरकार की आवाज नहीं निकली जब जनता ने ज्यादा हल्ला मचाया तो उल्टा ही धूर्त मक्कार ने बिना चीन का नाम लिए कह दिया कि हमारी सीमाएं सुरक्षित है हमारे यहां किसी ने अतिक्रमण नहीं किया है उससे न केवल चीन बल्कि पाकिस्तान नेपाल म्यांमार बांग्लादेश श्रीलंका तक के जिसकी सीमाओं मेंभूमि हड़प करने के सबके हौसले बुलंद कर दिये।

(शेष पेज 2 पर)

साप्ताहिक समय माया

# चीन को लाल आंख तो दूर, नेपाल हड़प रहा देश की भूमि

पेज 1 का शेष

अब हालात यह है की नेपाल जो हमारे टुकड़ों पर पलटा था हमारी भूमि पर कब्जा कर चुका है उसके संबंध में एक रिपोर्ट भारत की 7100 एकड़ जमीन पर नेपाल का कब्जा; एसएसबी को एक्शन की मनाही, प्रशासन को बोलने की इजाजत नहीं। जिस नेपाल को भारत सरकार ने मित्र मानकर गले से लगा रखा है, उसी मित्र ने बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले की लगभग 7100 एकड़ जमीन पर कब्जा जमा लिया है। ये सिलसिला अब भी तेजी से जारी है। वाल्मीकि नगर में सुस्ता, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के जंगल और गोवर्धना में शिवालिक रेंज की पहाड़ियां सहित कई ऐसे इलाके हैं, जहां अवैध कब्जा बढ़ रहा है। यहां पट्टे भी काटे जाने की तैयारी है। इस इलाके के डीएम डॉ. निलेश रामचंद्र देवर कहते हैं कि यह अंतरराष्ट्रीय मसला है, जबकि डीएफओ गौरव ओझा मानते हैं कि जमीन पर अतिक्रमण है। इस स्थिति का फायदा उठाकर लोग दोहरी नागरिकता का लाभ ले रहे हैं। जंगल से करोड़ों रुपए पेड़ काट दिए गए हैं।

सबसे ज्यादा प्रभावित सुस्ताः अब तो नेपाल का त्रिवेणी थाना भी सुस्ता में आ चुका है। अस्पताल, स्कूल, सड़क तक बना दी गई है। वीटीआर जंगल और गोवर्धना में शिवालिक रेंज की पहाड़ियां भी थीं, जिस पर अब नेपाल का दावा है। आज भी सुस्ता में बसने वाले 95 फीसदी लोग भारतीय हैं।

## इन 5 जगहों पर भी नेपालियों का कब्जा

1) मौजा ठाड़ी में 12 चादर में ठाड़ी, नर्सरी, बड़ा ठाड़ी, छोटा ठाड़ी गांव का रकबा 7378 एकड़ है, जिसमें 3000 हजार एकड़ पर कब्जा।
2) मौजा रमपुरवा में 2 चादर में रमपुरवा, हजमटोला, खडंजाटोला गांव का रकबा 900 एकड़, जिसमें 400 एकड़ पर कब्जा।
3) मौजा परसौनी में 2 चादर में सुस्ता, रोहुआ टोला, भेड़िहारी आदि गांव का रकबा 2351 एकड़, जिसमें 2300 एकड़ सुस्ता के नाम पर कब्जा।
4) मौजा बलगनवा में कई चादरों में आधा दर्जन गांव बसे हैं। इसका रकबा 3487 एकड़ है, जिसमें 1400 एकड़ नेपालियों के कब्जे में है।
5) सबसे ऊंची चोटी सोमेश्वर स्थित नो मेन्स लैंड पर भी पांच साल पहले नेपालियों ने झंडा लगा दिया। वहां नेपाली प्रहरी और एसएसबी दोनों है। चंपारण के वीटीआर और कई ऐसे भूभाग हैं, जहां नो मेंस लैंड है ही नहीं और नेपालियों ने कब्जा कर लिया है।

## नेपाल को लेकर चुप है सरकार

नेपाल की ओर से लगातार अतिक्रमण के बाद भी भारत सरकार ने कोई कदम नहीं उठाए हैं। 1815 की संधि में जो फैसला हुआ, उसमें 1960 की संधि में ढील दे दी गई। 2005 में जो संधि हुई, उसमें भारत सरकार नेपाल के प्रति और नरम हो गई। स्थानीय स्तर पर सीमा विवाद को लेकर 2006, 2006 और 2007 में कई समझौते हुए। साल में एक-दो बार दोनों देश के सीमावर्ती जिलों के अधिकारी बैठक करते हैं पर निष्कर्ष नहीं निकलता।

## दोहरी नागरिकता का लाभ ले रहे सुस्ता के निवासी

लोगों ने सुस्ता की भूमि की बंदोबस्ती भी नेपाल सरकार से करा ली है। बुनीलाल केवट, दुखीलाल केवट, लल्लू केवट, नृव कुमारी गुरड़ आदि को आधार कार्ड से मुक्त कर दिया है। उन्हें दोहरी नागरिकता का लाभ मिलता है। नेपाल में वहां के कागजात और भारत में यहां के कागज दिखा देते हैं।

## वीटीआर में तीन ओर से बना रहे सड़क

सुस्ता के एक ओर गंडक और तीन ओर से भारतीय भूभाग है। यहां मुन्ना खां की भी जमीन है। यहां तीनों ओर से सड़क निर्माण हो रहा है। ताकि भारत में और अंदर तक घुसा जा सके। लोग बताते हैं कि धनैया रेता और नेपाल अधिग्रहित सुस्ता और गंडक के तट पर 40 साल पहले तक जंगल थे। जब भारतीय अपराधी सुस्ता में आकर बसे तो वीटीआर के जंगल काटकर जबरदस्त अतिक्रमण करने लगे।

## इवीएम कलेक्टर, चुनाव आयोग से आम तक

पेज 8 का शेष

हमेशा की तरह पिछले 10 साल से सारे भ्रष्टाचारी बर्बादी जालसाजी करने पर जनता आवाज उठाती है तो संबंधित अधिकारी से लेकर मोदी तकसाथ झूठ बोलकर कह देते हैं नहीं ऐसा कुछ नहीं है अभी जैसा कि मोबाइल की कनेक्टिविटी ईवीएम सिपाही जाने और सीट जीत जाने के कांड में घोर भ्रष्ट मक्कार सूकर जालसाजों का गिरोह चुनाव आयोग मेंसारे सच को निकलते हुए बोल दियाकी एवं सेमोबाइल कनेक्ट नहीं हो सकताअगर औकात है तो किसी भी मतदान मशीनों की जनता के सामने किसी कंप्यूटर विशेषज्ञ सेजांच क्यों नहीं करवाई जाती जब-जब जांच करवाने का सवाल उठता है और जो व्यक्ति बोलता है उसके घर पर गुंडे बदमाश भेज कर डरा धमका कर उसका मुंह बंद कर रही है। मोदी सरकार पिछले 10 सालों से कब तक चांडाल जालसाजों देश को बर्बाद करके खुश होते रहोगे। मौत तुम्हारी भी निश्चित है अमरफल खाकर कोई नहीं आया।

# विश्व के हर वर्ग की जनता, व्यवसाय, उद्योग, धंधे, धर्म, सरकारें गुलाम

पेज 1 का शेष

दोनों ही मामले सिर्फ़ पुरानी चोरी हैं। क्या ऑनलाइन व्यक्तिगत डेटा गोपनीयता के बारे में बात करना शायद व्यक्तिगत डेटा की तस्करी के उस बुरे पहलू से ध्यान हटाने का एक तरीका है जो सालाना 250+ बिलियन डॉलर X₹85= 212.5 लाख करोड़ का बाजार बन गया है?

दरअसल यहाँ जो कुछ भी हो रहा है वह वास्तव में व्यवहार पर नियंत्रण के बारे में है, विशेष रूप से क्रय व्यवहार पर। चाहे व्यवहारिक विपणन के माध्यम से हो या प्रत्यक्ष धमकी के माध्यम से, ऑनलाइन दुनिया हमारी मान्यताओं को आकार दे रही है, यह तय कर रही है कि हम कैसे और क्या उपभोग करते हैं और नियमों को लागू करते हैं। मैंने हाल ही में प्रकाशित एक लेख में इस तर्क को अधिक विस्तार से रखा है। यह समय व्यक्तिगत गोपनीयता के बारे में ऑनलाइन बात करना बंद करने और इसके बजाय उस चीज़ का उल्लेख करना शुरू करने का है जिसे हम अपने दैनिक जीवन में तेज़ी से सामान्य बना रहे हैं, जो डिजिटल या अंकीय गुलामी से कम नहीं है। लेकिन, निश्चित रूप से 'गुलामी' मुद्दे को बढ़ा-चढ़ाकर पेश कर रही है? यह एक ऐसा शब्द है जो मौलिक मानवाधिकारों के घृणित उल्लंघन का वर्णन करता है, और इसलिए इसे लापरवाही से लागू नहीं किया जाना चाहिए। फिर भी, जैसा कि मैंने इस शब्द को खोलना शुरू किया, परंपरागत रूप से गुलामी को किसी इंसान को 'संपत्ति' या 'वस्तु' के रूप में रखने के कृत्य के रूप में परिभाषित किया जाता था। हाल ही में पारंपरिक परिभाषा के लिए 'चैटल गुलामी' और 'आधुनिक गुलामी' के बीच अंतर किया गया है। उत्तरार्द्ध, जिसमें सेक्स ट्रैफिकिंग जैसी प्रथाएं शामिल हैं, में दास के वास्तविक नियंत्रण के रूप में 'स्वामित्व' के विचार को शामिल किया गया है, न कि दास को कानूनी रूप से स्वामित्व वाली वस्तु के रूप में। 'डिजिटल गुलामी' में 'चैटल' और 'आधुनिक' गुलामी दोनों के पहलू हैं। और जो इस व्यापार को सक्षम कर रहा है वह ट्रांस-अटलांटिक दास व्यापारियों के नौकायन जहाज, बंदूकें, चाबुक और जंजीरें नहीं हैं, बल्कि निगरानी तकनीक, व्यक्तिगत डेटा तस्करी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) की अपवित्र तिकड़ी है।

## किसी अन्य मनुष्य को संपत्ति के रूप में अपनाना

यह तर्क 'स्व-अलगाव' की अवधारणा के दो संस्करणों के इर्द-गिर्द घूमता है। संपत्ति कानून में, कोई चीज़ 'अलगाव योग्य' होती है अगर वह 'बेची जा सकने वाली' हो या एक मालिक से दूसरे मालिक को 'अलग' की जा सके। 'स्व' को किसी तरह शरीर के साथ स्थित माना जा सकता है। इसे कभी-कभी 'शरीर-विषय' कहा जाता है। सवाल उठता है कि क्या 'शरीर-विषय' अलगाव योग्य है या कभी अलग होना चाहिए। जबकि शरीर-विषय भौतिक और मनोवैज्ञानिक दोनों भागों से बना होता है, कानून मुख्य रूप से भौतिक शरीर से संबंधित है, खासकर शरीर के अंगों की बिक्री और सरोगेसी जैसे क्षेत्रों में।

हालाँकि, शरीर-विषय एक ऐसी दुनिया में मौजूद है जिसमें स्मृति, ज्ञान, विश्वास, भावनाएँ, इतिहास और पहचान शामिल हैं। हम तेजी से पहचान रहे हैं कि कई लोगों के लिए शरीर-विषय जिस दुनिया में रहता है, उसमें आभासी दुनिया शामिल है जिसे हम इंटरनेट कहते हैं। हम इस आभासी दुनिया से प्यार करते हैं, नफरत करते हैं, खोज करते हैं, सीखते हैं और मोहित हो जाते हैं। यह सभी ऑनलाइन शरीर-विषय गतिविधि पूरे इंटरनेट में डिजिटल स्टोरेज फ़ार्म में भौतिक अस्तित्व रखती है। मस्तिष्क के इलेक्ट्रो केमिकल तंत्रिका मार्गों की तरह, ये डेटा स्टोरेज फ़ार्म डिजिटल रूप से ट्रैक करते हैं, और इस आभासी दुनिया में शरीर-विषय की स्मृति, व्यवहार, संबंधों और यात्रा को थोड़ा-थोड़ा करके बनाए रखते हैं।

जब यह डेटा सरकारों या निगमों द्वारा कानूनी या अवैध रूप से, अस्पष्ट और लंबे अनुबंधों, चालाकी, हेरफेर या सिर्फ चोरी के माध्यम से हासिल किया जाता है, तो शरीर-विषय स्वामित्व की दृष्टि से गुलाम बन जाता है। जुड़े हुए व्यक्तिगत डेटा, बलपूर्वक और स्वचालित सूचना एकत्रण, और 'हमेशा के लिए भंडारण' के संयोजन ने नई तरह की सूचना 'दास मालिकों' के उदय को सक्षम किया है। व्यक्तिगत डेटा का खनन किया जाता है, उसे वस्तु बनाया जाता है, संपत्ति बनाया जाता है और तस्करी की जाती है। व्यापारी कहते हैं कि उन्होंने जो भी व्यक्तिगत डेटा निकाला है वह एक 'बिना स्वामित्व वाला' कच्चा संसाधन है। कुछ हद तक तेल की तरह, परिणामी वस्तु का वाणिज्यिक मूल्य और स्वामित्व स्वयं उन लोगों में निहित होता है जो इसे एकत्र (निकालते) और परिष्कृत करते हैं। हालांकि तेल के विपरीत

## किसी अन्य मनुष्य को नियंत्रण में रखना

इस तर्क में एक संभावित कमजोरी यह है कि निगम और सरकारें गलत तरीके से स्वयं की संपत्ति को 'गुलाम' बना रही हैं, क्योंकि इसमें दार्शनिकों द्वारा 'आवश्यकतावाद' कहे जाने वाले तत्व की गंध आती है। आज की दुनिया में, कौन एक आवश्यक 'अच्छे जीवन' को परिभाषित कर सकता है जो हर व्यक्ति के मूल्यों को दर्शाता है? आधुनिक दृष्टिकोण व्यक्तियों के इस विचार का समर्थन करता है कि उन्हें यह कहने का अधिकार है कि उनके लिए क्या अच्छा है। इसलिए तर्क की एक संभावित पंक्ति यह है: 'अगर मैं चाहता हूं कि मेरा व्यक्तिगत डेटा कैप्चर और तस्करी हो, और मेरे कार्य एल्गोरिदम द्वारा संचालित हों, तो मुझे कौन बताएगा कि मैं गुलाम हूं?'

इस आलोचना से बचने के लिए, हमें दूसरे प्रकार के 'स्व-अलगाव' पर विचार करना चाहिए - जो स्व-संपत्ति पर आधारित नहीं है, बल्कि किसी व्यक्ति के अपने स्वायत्त जीवन जीने के रास्ते में आने वाली बाधाओं पर आधारित है। हम जिस स्तर के आत्म-अलगाव का अनुभव कर सकते हैं, वह अस्थायी बाधाओं का सामना करने से लेकर पूर्ण वर्चस्व का अनुभव करने तक होता है, जो कि गुलामी है। डिजिटल दुनिया में, व्यक्तिगत डेटा एकत्रीकरण और तस्करी के परिणामस्वरूप होने वाली आत्म-अलगाव वाली तृतीय-पक्ष प्रथाएँ सीधे 'डिजिटल गुलामी' की ओर ले जा सकती हैं, क्योंकि नागरिक या उपभोक्ता की एजेंसी और इच्छा को सक्रिय रूप से छिपे हुए तरीकों से नष्ट किया जाता है, और जबरदस्ती के स्तर में वृद्धि होती है। निगमों और सरकारों दोनों के लिए एकत्रित और पुनः-उद्देश्यित व्यक्तिगत डेटा को इतना मूल्यवान बनाने वाली बात यह है कि यह क्रमशः उपभोक्ता बिक्री में वृद्धि या राज्य के साथ अधिक नागरिक अनुपालन की दिशा में व्यवहार को आगे बढ़ाने में भूमिका निभाता है। व्यक्तिगत डेटा ऑनलाइन सोशल मार्केटिंग, प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स, अनुपालन 'विज़ाड्र्स', BDAI (बड़ा डेटा और कृत्रिम बुद्धिमत्ता), और व्यवहार अर्थशास्त्र/नज रणनीतियों को खिलाने वाले एल्गोरिदम की जीवनरेखा है।

इन गतिविधियों के उदाहरण रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा हैं। किसी व्यक्ति के ऑनलाइन (और कभी-कभी ऑफ़लाइन) इतिहास के आधार पर लक्षित 'व्यवहारिक' ऑनलाइन विज्ञापन का सबूत लगभग हर उददुत खोज में स्पष्ट रूप से मौजूद है। सरकारी और वाणिज्यिक दोनों ही प्रणालियाँ सूचना एकत्र करने के लिए ङअनिवार्य फ़ील्ड के उपयोग के साथ न्यूनतम सूचना-एकत्रण आवश्यकताओं को लगातार पार करती हैं - यूरोपीय संघ की हालिया उअईं पहल की महत्वाकांक्षाओं के बावजूद। जहाँ इस तरह का डेटा कानूनी रूप से एकत्र किया जाता है, वहाँ नागरिक/उपभोक्ता को अनिवार्य रूप से विस्तारित अनिवार्य कानूनी बॉयलरप्लेट और गोपनीयता नीति के नोटिस प्रस्तुत किए जाते हैं, जिन्हें हममें से अधिकांश लोग या तो बिना पढ़े स्वीकार कर लेते हैं या इसके वास्तविक निहितार्थों को समझने में विफल हो जाते हैं। प्रलोभन और जालसाज़ी के बीच की महीन रेखा ऑनलाइन काफ़ी हद तक अनियंत्रित और अनियमित है।

पश्चिमी सरकारें विशेष रूप से ऑनलाइन नागरिक 'सेवाओं' के लिए असीम उत्साह दिखाती हैं। ऑस्ट्रेलिया में सामाजिक सुरक्षा एजेंसी, सेंटरलिंक ने एक विवादास्पद ऑनलाइन अनुपालन हस्तक्षेप (ओसीआई) प्रणाली का अनुसरण किया, जिसे बोलचाल की भाषा में ' रोबो-ऋण' कहा जाता है। यह व्यक्तिगत डेटा के एकत्रीकरण और खनन का एक प्रमुख उदाहरण था , जिसे विभिन्न उद्देश्यों के लिए नागरिकों से एकत्र किया गया था, ताकि ऐसे एल्गोरिदम को बढ़ावा दिया जा सके जो अनुपालन व्यवहार को मजबूर करते हैं। सामाजिक कल्याण प्राप्तकर्ता की स्वायत्तता और अपने जीवन को चलाने की क्षमता को जबरन संलग्नता, एल्गोरिदम में पारदर्शिता की कमी और नागरिकों को ऑनलाइन प्रणाली के माध्यम से वापस जाने की आवश्यकता के द्वारा शिकायतों को कम करने की नौकरशाही रणनीति के माध्यम से कम किया गया था। यह देखने के लिए कि इस तरह का सरकारी व्यवहार कहां तक पहुंच सकता है, कॉर्पोरेट वफादारी कार्यक्रमों के 'डार्क ट्विन' पर विचार करें

## अंत में, स्लोवेनियाई दार्शनिक स्लावोय जिजेक की चेतावनी को याद करना उचित होगाः

'इस नियंत्रण और हेरफेर के पूरे दायरे को समझने के लिए हमें निजी निगमों और राजनीतिक दलों के बीच संबंधों से आगे बढ़कर गूगल या फेसबुक जैसी डेटा प्रोसेसिंग कंपनियों और राज्य सुरक्षा एजेंसियों के बीच की अंतर्क्रिया को समझना होगा। ... उभरती हुई समग्र छवि ... सामाजिक नियंत्रण के नए रूपों की एक पर्याप्त और भयावह दृष्टि प्रदान करती है जो बीसवीं सदी के अच्छे पुराने 'अधिनायकवाद' को नियंत्रण की एक आदिम और अनाड़ी मशीन बनाती है।'

### खनन से खनका रहे मंत्री सचिवों से निरीक्षक तक

# रेती, खनन, नेता माफिया विभागीय संरक्षण में अवैध मोटी कमाई

## अधिकांश मंत्रियों, नेताओं से लेकर सरकारी ठेकेदार कर रहे धरा खोखली

मध्य प्रदेश में भुखेरा जन पार्टी की सरकार के अधिकांश मंत्री विधायक नेता नर्मदा वह अन्य सभी नदियों की रेती खनन से लेकर, कच्ची मुरम, गिट्टी, पत्थर भूगर्भ से लेकर भूतल पर स्थित प्राकृतिक पहाड़ों को साफ करके न केवल इंदौर वेः चारों तरफ वरन अलीराजपुर बड़वानी बुरहानपुर धार खंडवा खरगोन, झाबुआ उज्जैन आगर मालवा देवास मंदसौर नीमच शाजापुर रतलाम के साथ पूरे प्रदेश के हर जिले में गौड खनिजों वृहद स्तर के कोयला तांबा लोहा अभ्रक आदि अयस्कों से लेकर से लेकर प्रदेश में हीरे की पन्ना छतरपुर में खदानें पाई जाती है वहां पर भी अवैध खनन करवाने में घोर भ्रष्ट जालसाज जिला कलेक्टर से लेकर जिला खनिज अधिकारी व खनिज निरीक्षकों से वहां बैठे नगर सेवा के सिपाहियों और चपरासी तक की भारी भूमिका होती है। यही कारण है, अवैध खनन से लेकर कच्ची मोरम गिट्टी पत्थर जैसे गोद खनिजों की अधिकांश ठेकेदार छोटी-छोटी खदानें लेकर कई गुना ज्यादाकी खुदाई करके मोटी कमाई करते हैं और रेत के मामले में तो आप देख ही रहे हैं चंबल की और नर्मदा की रेट के मामले में किस प्रकार से अवैध कारोबार चलता है और जो भी निरीक्षक जिला अधिकारीयों कलेक्टर उप जिलाधीश सहायक जिलाधीश आदि को पकड़ने पहुंचते हैं तो वह नेता माफिया उनकी हत्या करने से भी नहीं चूकते पर इन सब को पीछे पालने वाले विभाग के कर्मचारी और अधिकारी ही होते हैं।

वैसे खनिज मंत्री भी पुराना खनिज माफिया ही बनाया जाता है वैसे वर्तमान में पूर्व के भू कॉलोनी शराब खनन आदि के बड़े माफिया वर्तमान के मुख्यमंत्री मोहन यादव खनिज साधन मंत्री भी हैं।इस विभाग के प्रधान सचिव निकुंज कुमार श्रीवास्तव भारतीय प्रताड़ना सेवा अधिकारी वसूली तो कर रहे हैं पर प्राप्त जानकारी के अनुसार डकैती नहीं डाल रहे पर जहां तक संचालक अनुराग चौधरी भारतीय प्रताड़ना सेवा अधिकारी जो पूर्व के स्वास्थ्य विभाग के आयुष्मान स्वास्थ्य लाभ योजना के भ्रष्टाचार और डकैती कांड के सरगना रहे हैं। वर्तमान में खनिज विभाग के प्रशासक और संचालक भी हैं।

उज्जैन देवास धार्मिक रहे खनिज अधिकारी खतेड़िया के बारे में तो आप जानते हैं कि उसके पास खुद की पोकलेन मशीन और गिट्टी प्लांट थे करोड़ों रुपए की अवैध संपत्ति का मालिक निकला उसे सस्पेक्ट निलंबित याजांच बैठा करबर्खास्त नहीं किया गया जब-जब पकड़ा जाता हैतब तो वह इंदौर के संयुक्त संचालक खनिज विभाग में अटैच हो जाता है। इंदौर की खनिज अधिकारी खन्ना के मामले में की समाचार पत्रों में काफी छप चुका है वर्तमान के चौहान को यहां से हटकर भोपाल में टच कर दिया गया है और जिलाधीश स्टार की अधिकारी को इंदौर में प्रवेश किया जाना है यहां बैठे दो खनन निरीक्षक चैन सिंह डामोर अपने भ्रष्टाचार के कारण जिलाधीश द्वारा निर्वाचन में अटैच कर दिए गए हैं और दूसरा घोर जालसाज व भ्रष्ट अवैध खनन को न केवल ठेकेदारों बल्कि लोक निर्माण विभाग लोक स्वास्थ्य यांत्रिकीय, नगर निगम पालिकाओं परिषदों के ठेकेदारों के साथ राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण वह अन्यकार्य विभागों को यह निरीक्षक जयदीप नामदेव संरक्षण देकर चारों तरफ से जिलाधीश आशीष सिंह व उनके मातहतों के अंतर्गत कार्य करते हुए मोटी वसूली कर रहा है। देवास की खनिज अधिकारी रश्मि पांडे जिसके पास पूरी नर्मदा पट्टी है नेमावर से लेकर बड़वाह की सीमा तक जहां पर पूरी नर्मदा की रेत का खनन किनारो पर वैध अवैध सतत किया जा रहा है। जितने की खदान ली जाती है। उससे कई गुना ज्यादा रेती का उत्खनन करके

बिना रॉयल्टी चुकाये बिक्री कर दी जाती है। और बदले में वहां के निरीक्षकों को यथोचित धन देकर साध के रखा जाता है। यही कारण है, की खनिज अधिकारी पांडे किसी से बात नहीं करती हैं। न हीं सूचना के अधिकार में जवाब व जानकारी देती है। उज्जैन की जिला खनिज अधिकारी देविका परमार के पास भी उज्जैन में रेती से लेकर अन्य गौड खनिजों की पूरे जिले में सैकड़ो खदानों में भारी मात्रा में अवैध उत्खनन किया जा रहा है। यहां पर भी खनिज निरीक्षक संजय सोलंकी अधिकांश वैध और अवैध खदानों में ठेकेदारों को खुली छूट देकर मोटी वसूली कर रहा है। आगर मालवा में खनिज अधिकारी राम सिंह उइके, खनिज निरीक्षक खुशबू वर्मा, मंदसौर में श्रीमती भावना सेंगर प्रभारी जिला खनिज अधिकारी खनिज निरीक्षक टीनू डाबर नीमच में प्रभारी खनिज अधिकारी डॉ रश्मि श्रीवास्तव और सहायक खनिज अधिकारी गजेंद्र सिंह डाबर, रतलाम में जिला खनिज अधिकारी आकांक्षा पटेल और खनिज निरीक्षक देवेंद्र चिडार, शाजापुर में जिला खनिज अधिकारी आरिफ खान और निरीक्षक गोविंद पाल, बड़वानी में प्रभारी जिला खनिज अधिकारी घनश्याम धनगर, खनिज निरीक्षक शांतिलाल निनामा बुरहानपुर में खनिज अधिकारी सोनम सिंह तोमर व सचिन वर्मा सहायक खनिज अधिकारी कामना गौतम धार में खनिज अधिकारी जूवान सिंह भिड़े, खनिज निरीक्षक जगन सिंह भिंडे व संदेश पिपलोदिया, झाबुआ में खनिज अधिकारी राकेश कनेरिया खनिज निरीक्षक शंकर कनेश खंडवा में उप जिलाधिकारी सचिन वर्मा खनिज निरीक्षक कंचन दांडेकर के साथ पूरे प्रदेश के जिलों के हर खनिज विभाग में जितने भी खनिज अधिकारी और निरीक्षक बैठाये गए हैं। सब मोटा पैसा देकर ही पदस्थ हुये हैं। स्वाभाविक है, वैध अवैध खदानों में भरपूर दोहन करवा के ही मोटी कमाई कर जिला कलेक्टर से लेकर विधायकों, संचालक, प्रधान सचिव और खनिज मंत्री व मुख्यमंत्री मोहन यादव को पहुंचा रहे होंगे।

सभी जिलाधीशों से लेकर खनिज अधिकारियों निरीक्षकों को सभी केंद्र के केंद्रीय लोक निर्माण विभाग, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, राष्ट्रीय भवन निर्माण प्राधिकरण के साथ अन्य सरकारी विभागों व राज्यों के कार्य विभागों मैं लोक निर्माण की भवन एवं पथ, भवन, सेतु निर्माण, मध्य प्रदेश सड़क डकैती निगम, जल संसाधन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण, पुलिस हाउसिंग, मध्य प्रदेश गृह निर्माण मंडल, ग्रामीण यांत्रिकी सेवाएं से लेकर अधिकांश ग्राम पंचायतों से नगर निगम पालिकाएं परिषद आदि की वेव साइटों और मैदानी कार्यस्थलों पर जाकर भी निरीक्षण करना चाहिए कितने टेंडर हुए कितने टेंडर में जो काम हुए उनमें कितनों ने गिट्टी मिट्टी पत्थर आदि का उपयोग किया परंतु विभागीय लोगों के साथ मिलकर रॉयल्टी की चोरी का पैसा हजम कर गए। यहां पर पूरे प्रदेश में सभी कार्य विभागों में भी खुलकर ठेकेदार जालसाजी कर आधी अधूरी रॉयल्टी चुका कर हजम कर राजस्व को हर महीने की हानि पहुंचाते हैं। इंदौर में ही मांगलिया में देवास मार्ग के कोने परजो बड़ा गड्ढा बना हुआ है उसमें पिछले चार महीनों से लगातार राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण या अन्य कोई ठेकेदार पोकलेन मशीनों से मुरमऔर पत्थरों का अवैध खनन कर रहा है। जिसका वीडियो बनाकर भी डाला गया था इंदौर प्रशासन ने कोई ध्यान नहीं दिया।

दूसरी तरफखनन से प्रदेश केनाखून नदियों के किनारे बल्कि कई पहाड़ों व क्षेत्र की पहाड़ियों को वैध अवैध खनन से काटकर साफ कर दिया गया। तो उनमें तो पुनःमिट्टी याराज से पानी बनाया जा सकता पर जहां खनन से सैकड़ो फुट गहरे लंबे चौड़े लाखों घन फिट के गड्ढे खोद दिए गए। ऐसी हजारों खजाने मध्य प्रदेश में अत्यधिक घातक हो जाती है और बरसात में पानी भरता है और बच्चे नहाने जाते हैं तो हर साल दो चार पांच बच्चों से लेकर बड़ों तक की मृत्यु हो जाती है जिसके लिए पूर्ण से खनिज विभाग और जिले का संबंध कलेक्टर जिम्मेदार होता हैउसके साथ ही प्रदूषण नियंत्रण मंडल जो ऐसी खनिजों को निकालने के बाद जमीनों के समतलीकरण के लिए जिम्मेदार है वह भी बड़े वैध तरीके सेली खदानों के ठेकेदारों से मोटी वसूली कर चुप हो जाता है। फिर खनन सेन केवल नदियों के किनारे बर्बाद होते हैं बल्कि खनन के लिए हजारों पेड़ों की बड़ी भी चलाई जाती है और अभी छतरपुर पन्ना मैं हीरा खनन के लिए जो बिरला को ठेका दिया गया है उसमें भी लाखों पेड़ों की कटाई कर बलि चढ़ा भूमि साफ कर खुदाई की जानी है तो वॉच आवाआईडीएच उत्खनन करने वाले ठेकेदार माफियाओं से लेकर खनिज अधिकारियों निरीक्षकों से जिला कलेक्टर तक को देखना चाहिए कि हम पर्यावरण बर्बाद करके आने वाली पीढीयो के लिए क्या छोड़ कर जा रहे हैं। इसका भी ध्यान रखा जाना चाहिए। अमेरिका ब्रिटेन अपनी धरती से खनन करके कुछ भी नहीं निकालते वह विदेश से खनिजों का आयात कर अपना काम चलाते हैं। ताकि भविष्य में आपातकाल में उन खनिजों का उपयोग किया जा सके। परम परम भूखे भेड़ियों की तरह देश के प्राकृतिक संसाधनों का अधिकतम दोहन करके कमाई कर पर्यावरण बर्बाद करके आगे आने वाली पीढियां के लिएक्या छोड़ कर जाने वाले हैं। इसका ध्यान सबको रखना चाहिए। हमारे पूर्व भी धरती थी। हम मानव धरती पर कुछ वर्षों के मेहमान होते हैं और हमें भी जाना पड़ता है और आने वाली पीढ़ियां हमारे कुकर्मों को भोगकर परेशान होकर गलियाती रहेंगी। यह कौन चाहता है? पर हमारीभूत नेता मंत्रियों खनन ठेकेदारों और उनको संरक्षित करने वाले जिम्मेदार अधिकारियों को इससे कोई मतलब नहीं।

### उद्यानिकी विभाग में केंद्र व राज्य की योजनाओं में

# अधिकांश कार्य एवं उत्पादन कागजों पर, धन बंदर बांट में हजम

**मप्र उद्यानिकी में एसीएस पीएस संचालक से ग्रामीण उद्यान की अधिकारी तक भ्रष्ट कागजों में अधिकांश काम**

मध्य प्रदेश का उद्यानिकी विभाग अपने भ्रष्टाचार को लूट और डकैती के लिए प्रारंभ से ही कुख्यात रहा है वर्तमान में बैठा अपर मुख्य सचिव आसींद मिश्रा जिसमें विभाग में गया लंबी चौड़ी डकैती डाली इसके और शिवराज सिंह चौहान की साझेदारी में विदेश में भी आने को प्रकार के व्यवसाय हैं यह अपनी डकैती के लिए हर विभाग में कुख्यात रहा है। वर्तमान में कृषि और उद्यान की विभाग का सह कृषि उत्पादन आयुक्त भी है। जिसका मूल उद्देश्य बहुराष्ट्रीय कंपनियों के फायदे के लिए प्रदेश के किसानों का हर तरह से शोषण करना और बर्बाद करना ही है कुशको की फसलों का अधिकतम लाभ देश-विदेश की बहुराष्ट्रीय कंपनियों को मिले यह खासतौर से उसी के लिए बैठाया गया है। प्रधान सचिव सुखबीर सिंह की ज्यादा भ्रष्टाचार की खबर सुनने में नहीं आई। परंतु उद्यान की तथा खाद्य संस्करण विभाग का संचालक शशि भूषण सिंह संचालक हैजो भारतीय प्रताड़ना सेवा का अधिकारी है। जिस कृषि के बारे में केवल भ्रष्टाचार करने और बटोरने की जानकारी है जबकि उसके पूरे विभाग में उचित तरीके से पदोन्नतियां व भर्तीयां ना होने के कारण अधिकांश पूरे प्रदेश में सभी सहायक उप और संयुक्त संचालक पदों से लेकर वरिष्ठ उद्यान की अधिकारियों के पदों पर 90% मोटा प्रभार लेकर प्रभारी अधिकारियों की पदस्थी की गई है। स्वाभाविक है, सब जलसाजिओ फर्जीवाड़े से ही वसूली करके मंत्री संत्री से लेकर संचालक प्रधान सचिव और एसीएस को महीना पहुंच पाएंगे।

मप्र उद्यानिकी विभाग में केंद्र की 6 व राज्य की 9 योजनाओं में धन का आवंटन किया जाता है **( शेष पेज 7 पर )**

साप्ताहिक समय माया

# मनचाही इच्छा पूर्ति के लिए
## सुबह आंख खुलते ही करें ये काम

हर इंसान का एक टाइम आता है। खैर, बुरा वक्त किसी को बता कर नहीं आता है। क्योंकि समय और परिस्थिति कभी भी एक जैसी नहीं होती है। समय केवल अपनी गति से चलता है और ऐसे में किसी इंसान का कभी अच्छा वक्त आता है तो कभी बुरा भी आ सकता है।

अच्छे समय आने पर हर कोई इंसान बहुत खुश होता है, मगर इस बीच कभी बुरा समय आ जाए तो वह खुद को संभाल नहीं पाते हैं। इसलिए ध्यान रखें उनके कुछ ऐसे काम जिन्हें नियमित रूप से कर लेने से बुरे वक्त को जल्दी टाला भी जा सकता है और जितना समय भी रहता है उस वक्त आपकी जिंदगी में सकारात्मक ऊर्जा का वास ही रहता है।

**ये काम नियमित करें**

शास्त्रों के मुताबिक मनुष्य को सुबह-सुबह उठकर किसी का चेहरा ना देखते हुए सबसे पहले अपने हाथों को चेहरे पर फेरना चाहिए। साथ ही अपने हाथों की रेखाओं को देखते हुए भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि उसका पूरा दिन सुखपूर्वक जाए।

इसके बाद इंसान को स्नान आदि कर लेने के बाद भगवान की पूजा करनी चाहिए और सूर्य भगवान को जल चढ़ाना चाहिए। अगर आपके घर तुलसी का पौधा रखा हुआ है तो हर दिन उसकी पूजा जरूर करनी चाहिए। इसके साथ ही आप तुलसी में दीपक भी लगाएं।

खाना बनाते वक्त सबसे पहली रोटी गाय माता के लिए बनाएं और रोटी पर घी लगाकर गाय को खिला दें। ऐसा कर लेने से अन्नपूर्णा प्रसन्न होती हैं।

रात में सोने से पहले अपने द्वारा पूरे दिन में किए गए सभी कामों को याद करें और अगर आपने पूरे दिन में किसी इंसान का दिल दुखाया है या उसे परेशान किया तो भगवान से अपने किए की माफी मांगे।

शास्त्रों के मुताबिक अपने बड़ों का हमेशा सम्मान करना चाहिए। जो भी लोग अपने बड़ों का आदर सम्मान नहीं करते हैं उन लोगों पर कभी-भी लक्ष्मी का वास नहीं होता है। वहीं जो लोग बड़े-बुजुर्गों का सम्मान करते हैं उन पर भगवान का आशीर्वाद सदैव बना रहता है।

## जीवन में छायी है निराशा तो अपनाएं
# रोटी से जुड़े ये आसान उपाय

सनातन संस्कृति में गाय को पहली रोटी खिलाने की परंपरा है। ऐसा करना शुभ माना गया है और शुभ फल प्राप्ति के लिए यह विशेष उपाय भी है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कुंडली से जुड़े तमाम ग्रहों के दोषों को दूर करने के लिए रोटी से जुड़े उपाय बताए गए हैं। तो आइए जानते हैं रोटी से जुड़े वो ज्योतिषीय उपाय जो किसी भी इंसान की तकदीर बदलने में मददगार साबित होते हैं।

**दिन की पहली रोटी का उपाय**

घर की रसोई में पहली रोटी सेंकने के बाद उसमें शुद्ध घी लगाकर चार टुकड़े कर लें और चारों टुकड़ों पर खीर अथवा चीनी या गुड़ रख लें। इसमें से एक को गाय को, दूसरे को कुत्ते को, तीसरे को कौवे को और चौथे को किसी भिखारी को दे दें।

**रात की अंतिम रोटी का उपाय**

यदि आपके जीवन में शनि ने फैला रखी हो सनसनी या फिर काम में राहु-केतु अटका रहे हों रोड़ा तो रोटी का उपाय आपके लिए रामबाण साबित हो सकता है।

इन सभी ग्रहों की अशुभता को दूर करने के लिए रात के समय बनाई जाने वाली अंतिम रोटी पर सरसों का तेल लगाकार काले कुत्ते को खाने के लिए दें।

**इन्हें जरूर खिलाएं रोटी**

हमारे यहां अतिथि को देवता के समान माना गया है फिर वो रसूख वाला हो या फिर एक आम आदमी। यदि कोई निर्धन या भिखारी आपके घर आए तो आप उसे यथासंभव भोजन जरूर कराने का प्रयास करें।

**इस उपाय से दूर होगा राहु का रोड़ा**

यदि तमाम प्रयासों के बावजूद सफलता आपके हाथ नहीं लग रही है तो आप के लिए रोटी का यह उपाय वरदान साबित हो सकता है। काम में आ रही बाधाओं को दूर करने के लिए रोटी और चीनी को मिलाकर छोटे-छोटे टुकड़े चींटियों के खाने के लिए उनके बिल के आस-पास डालें। इस उपाय से आपकी बाधाएं धीरे-धीरे दूर होने लगेंगी।

वास्तुशास्त्र

## घर व ऑफिस में इस दिशा में
# लगाएं घड़ी

आप और हम सभी को घड़ियां ना केवल सही समय बताती है, बल्कि ये घड़ी हमारे अच्छे और बुरे दोनों समय में खूब योगदान भी देती हैं। वैसे क्या आप जानते हैं कि आपके ऑफिस या घर की दीवार पर टंगी हुई घड़ी आपके वक्त के बारे में बहुत कुछ बयां भी करती है। घड़ी को सही दिशा में लगाया जाए तो यह आपके लिए अच्छा समय भी लेकर आती है। वहीं घड़ी का गलत दिशा में लगा होना आपके लिए बुरा समय आने की ओर भी इशारा करता है।

दक्षिण दिशा की ओर सभी कार्यों को करने को अशुभ माना जाता है। इसलिए घड़ी को कभी भी दक्षिणी दीवार पर नहीं लगाना चाहिए। क्योंकि दक्षिण दिशा यम की मानी जाती है।

फेंगशुई में बताया गया है कि दक्षिण दिशा में घड़ी लगाने से राह जरूर अड़चनें आती हैं। इससे आपको नौकरी पर भी बुरा असर पड़ता है।

ध्यान रहे घर के मुख्य द्वार के ऊपर वाली दीवार पर भी घड़ी नहीं लगाएं क्योंकि इससे परिवार में लड़ाई-झगड़े होने का डर रहता है।

# पत्थरचट्टा का पौधा कैसे लगाएं

## इस औषधि से लाखों रुपये कमाने का तरीका

**भारतीय किसानों के बीच औषधीय पौधों की खेती बहुत लोकप्रिय हो रही है। आज हम आपको एक ऐसे पौधे के बारे में बताएंगे जिसकी खेती से किसान प्रतिवर्ष लाखों रुपए कमा सकते हैं। जी, जहां पत्थरचट्टा का पौध लगाकर किसान अपनी आमदनी में जोरदार वृद्धि कर सकते हैं। पत्थरचट्टा ( ब्रायोफिलम ) एक सामान्य तासीर वाला पौधा है जिसे किसी भी मौसम में खाया जा सकता है। आयुर्वेद का प्रचलन बढ़ने के साथ इस आयुर्वेदिक पौधे की मांग भी लगातार बढ़ रही है। ट्रैक्टर जंक्शन की इस पोस्ट में आपको पत्थर चट्टा पौधे कैसे लगाएं, पत्थरचट्टा पौधे की खेती, पत्थरचट्टा से कमाई आदि के बारे में विस्तृत जानकारी दी जा रही है।**

पत्थरचट्टा का पौध लगाने के लिए किसी बीज की आवश्यकता नहीं होती है। यह पौधा सिर्फ पत्तों से ही उगाया जा सकता है। पत्थरचट्टा के पौधे को छोटे गमलों में भी लगाया जा सकता है। पत्थरचट्टे के पौधों को गमले में भरी मिट्टी में डालना होगा। मिट्टी में डालने के कुछ दिनों बाद ही पत्थरचट्टा का पौधा उग आता है। इस पौधे की खूबी यह है कि मिट्टी में इसके पत्तों की किनारी डालने पर भी यह उग आता है। यहां आपको बता दें कि पत्थरचट्टा के नए पौधे टेराकोटा के बर्तनों में लगाए जाते हैं, जिनमें तल में जल निकासी छेद होते हैं।

### पत्थरचट्टे के फूल और पौधे

आपको बता दें कि पत्थरचट्टे के पौधे में फूल भी उगते हैं मुख्यतः बसंत और सर्दी के मौसम में आते हैं। इस अद्भुत पौधे में कई औषधीय गुण भी पाए जाते हैं जो कई रोगों में लाभ पहुंचाते हैं। अगर आप पत्थरचट्टे की खेती करना चाहते हैं तो आपको इसे नर्सरी से या ऑनलाइन खरीदना होगा। इसके बाद आप इसके पत्तों से जिनती चाहे उतनी खेती कर सकते हैं।

### पत्थरचट्टा के लिए मिट्टी

पत्थरचट्टा की खेती के लिए नम मिट्टी की आवश्यकता होती है। आपको नम मिट्टी के ऊपर एक पता रखना है। इसके बाद कुछ ही दिनों में पूर्ण विकसित पौधा तैयार हो जाता है। आप 60 प्रतिशत दोमट मिट्टी +20 प्रतिशत कोको पीट +20 प्रतिशत रेत के साथ पोटिंग मिक्स तैयार करके पत्थरचट्टा की खेती कर सकते हैं। पत्थरचट्टा के नाए पौधे विकसित होने पर नम मिट्टी में गिर जाते हैं। फिर यह नए पौधों के रूप में उगने लगते हैं।

### पत्थरचट्टा की खेती की खास बातें

पत्थरचट्टा के पौधे को रोजाना कम से कम 4 से 5 घंटे धूप की जरुरत होती है। ये पौधे अत्यधिक गर्मी तो सहन कर सकते हैं लेकिन पाला को नहीं सहन कर पाते और नष्ट हो जाते हैं। इसलिए इनको घर के अंदर रखना चाहिए या खेती में शेड के अंदर रखना चाहिए। पत्थरचट्टा में पानी डालने के भी कुछ नियम आपको फायदा पहुंचाएंगे। बसंत और गर्मी के दौरान जब मिट्टी 2 से 3 इंच की गहराई तक सूख जाए, तब इसमें पानी डालना चाहिए। विशेषज्ञों के अनुसार यदि ब्रायोफिलम के पौधों में फिल्टर पानी का उपयोग किया जाता है तो इसका विकास अधिक अच्छा होता है। पत्थरचट्टा के पौधे के समुचित विकास के लिए प्रति दो माह के दौरान एक बार आधा चम्मच बोन मील देना चाहिए।

### पत्थरचट्टा के पौधों में रोग नियंत्रण

पत्थरचट्टा के पौधों को समय-समय पर रोग व कीट से बचाव करना भी जरूरी है। पत्थरचट्टा के पौधे में संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए भूरे रंग के पत्ते को हटा देना चाहिए। इसके अलावा एफिड्स को भी हाथ से हटाना चाहिए। यदि पत्थर चट्टा का पौधा फफूंदी से संक्रमित हो जाता है तो इसे नियंत्रित करने के लिए पोटेशियम बाइकार्बोनेट का उपयोग किया जा सकता है।

### पत्थरचट्टा से कई बीमारियां होती है दूर

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पत्थरचट्टा औषधीय गुणों से भरपूर है। इसके सेवन से कई प्रकार की बीमारियां दूर होती हैं। इसे घर पर गमले में भी लगाया जा सकता है। इसके पत्तों का स्वाद खट्टा और नमकीन होता है। यह मूत्र विकार, संक्रमण, सिर दर्द, आंख, जख्म भरने, हाई ब्लड प्रैशर सहित कई रोगों में रामबाण का काम करता है। इसकी पत्तियों का रसा काढ़ा के तौर पर भी पिया जा सकता है। पत्थरचट्टा के सेवन से किडनी की पथरी, प्रोस्टेट ग्रंथि की बीमारी, खून का बहना, आदि रोग भी दूर होते हैं।

# चाइनीज लीची की खेती कर रही किसानों को मालामाल

**अधिकतर किसान ऐसी खेती करना पसंद करते हैं, जिसमें उन्हें कम लागत पर अधिक मुनाफा हो. ऐसे में कई किसान कंफ्यूज रहते हैं, कि उनके लिए कौन सी खेती करना सही रहेगा. अगर आप भी इस बात को लेकर कन्फ्यूजन है, तो ये खबर आपके लिए है. आज हम आपको बताएंगे चाइनीज लीची के बारे में, जिसकी खेती कर किसान हर साल लाखों का मुनाफा कमा सकता है.**

### चाइनीज लीची की खेती

**चाइनीज लीची को लाल लीची के नाम से भी जाना जाता है. यह भारत में काफी पसंद की जाने वाली चीज है. चाइनीज लीची की भारत ही नहीं विदेशों में भी काफी डिमांड रहती है.**

ज्यादा डिमांड होने की वजह से इसकी कीमत भी अच्छी खासी होती है. किसानों को इसकी खेती कर हर साल काफी मुनाफा होता है. बता दें कि चाइनीज लीची की खेती करने पर ज्यादा समय और मेहनत दोनों ही नहीं लगती है.

### किसानों को मिलेगा प्रॉफिट

**आप आम की बागवानी के साथ लीची की बागवानी भी कर सकते हैं. ज्यादा डिमांड होने की वजह से कई किसानों ने चाइनीज लीची की खेती करना शुरू कर दी है. किसान लीची की बागवानी ढाई से 3 महीने कर करीब 3 से 4 लाख तक का मुनाफा कमा सकता है. लीची की बागवानी करने के बाद किसानों को अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है.**

### लीची के प्रकार

वैसे लीची दो प्रकार की होती है एक तो शाही लीची तो वहीं दूसरी चाइनीज लीची. शाही लीची का स्वाद थोड़ा खट्टा होता है और यह तैयार होने में समय लगाती है. वहीं चाइनीज लीची कम समय में तैयार हो जाती है और स्वाद में मीठी लगती है. किसान दोनों की खेती कर अच्छा मुनाफा कमा सकता है. चाइनीज लीची की खेती करने पर कम लागत होती है लेकिन इसमें पानी थोड़ा ज्यादा लगता है. इस खेती में कीटनाशक दवाइयों का छिड़काव समय-समय पर करना पड़ता है.

### लीची की पैदावार

जानकारी के मुताबिक आप बारिश तक का इंतजार कर सकते हैं, क्योंकि बारिश होने के बाद पेड़ का फल थोड़ा मीठा हो जाता है. गर्मी में लू की वजह से लीची की पैदावार पर थोड़ा असर पड़ सकता है. इसलिए इसकी बागवानी करते वक्त आपको थोड़ा ध्यान रखना जरूरी होता है. चाइनीज लीची की बाजार में ज्यादा मांग है और इसकी कीमत भी अधिक होती है. इससे किसान को काफी प्रॉफिट हो सकता है. चाइनीज लीची अन्य किस्म की तुलना में अधिक उपज देती है. चाइनीज लीची की खेती किसानों के लिए काफी लाभदायक व्यवसाय हो सकता है. अगर आप इसकी खेती शुरू करने की सोच रहे हैं, तो यह आपके लिए बेस्ट ऑप्शन होगा.

साप्ताहिक समय माया

## देश की प्रगति में नेहरू की भूमिका मील का पत्थर

# विश्व में मात्र भारत जहां नेहरू की मिश्रित अर्थव्यवस्था ने दी सतत प्रगति

### पूंजीवाद जनता व देश का घोर शोषणकारी तो साम्यवाद मक्कारवाद का परिचायक

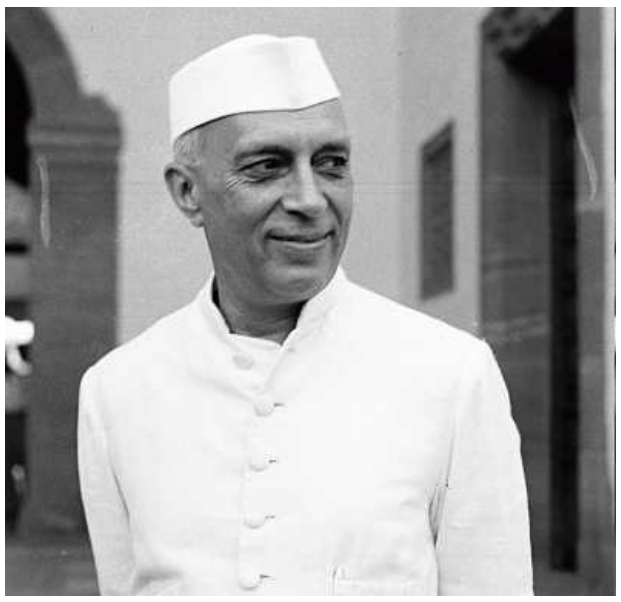

भारत में आजादी से पूर्व अंग्रेजों ने और देश के चंद पूंजीपतियों टाटा बिरला डालमिया आदि की सत्ता ने न केवल जनता बल्कि देश के प्राकृतिक व मानव निर्मित संसाधनों का भरपूर अपने हितों के हिसाब से दोहन किया। परंतु आजादी के बाद नेहरू ने जो ऑक्सफोर्ड से पढ़कर निकले थे साम्यवाद और पूंजीवाद की अच्छाइयों बुराइयों का उन्हें अच्छा अध्ययन था। इसलिए उन्होंने इस देश में पूर्ण पूंजीवाद और साम्यवाद को नकार दोनों की अच्छाइयों के साथ विशेष बुराइयों को ध्यान में रख देश की सतत प्रगति के लिए दोनों को मिलाकर मिश्रित अर्थव्यवस्था का रास्ता चुना। जो उनके और कांग्रेस स्वर्गीय इंदिरा गांधीऔर राजीव गांधी के रहते हुए देश को देश की जनता उनके प्राकृतिक व मानव निर्मित संसाधनों का भरपूर जनहित में उपयोग करते हुए देश की जनता के साथ देश को भी भरपूर प्रगति के अवसर उपलब्ध करवाये। जो अमेरिका और ब्रिटेन जैसै देशों को हजम नहीं हुआ। स्व. नेहरू ने रेलवे, विद्युत कंपनियों, सड़कों, बड़े प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर उद्योगों को राष्ट्र की संपत्ति मान सरकारी करण करके उनके विकास के साथ अनेकों भारी उद्योगों की आधारशिला रख उत्पादन प्रारंभ करवाया। भाखड़ा नांगल सरदार सरोवर जैसे वृहत बांधों की आधारशिला रखी। ताकि ना केवल विद्युत, बल्कि देश के कृषि उत्पादन को बढ़ाने देश के खेतों में पानी पहुंचानेसैकड़ो किलोमीटर लंबी नहरों का निर्माण करवाया।

नेहरू के दौर में 33 PSUs बने, इंदिरा गांधी के दौर में 66 PSUs बने, राजीव के दौर में 18 PSUs बने , मनमोहन के दौर में 23 PSUs बने, कांग्रेस के दौर में कुल 160 PSUs बनाये, अटल बिहारी वाजपेयी के दौर में भी 17 PSUs बने थे मोदी राज देश की बर्बादी का कँकाल बन गया? पुराना सब तहस-नहस हुआ और नया एक भी PSU नहीं बना। 5 साल में 3 तीन नीति आयोग, चीफ इस्तीफा देकर, भाग गए? सबसे बड़ा प्रूफ है? रंगा बिल्ला, सिर्फ देश बेचने, लूटने के  नीति पर फोकस किये हुए है। 30 जनकल्याण और प्रॉफिट वाली PSU कौड़ी भाव वैल्यू लगाकर, सिर्फ 02 मित्रो को बैंको से हैवी लोन दिलवाकर, बेच/लीज करके उनके नाम कर रहा है, और फिर उनके लोन टैक्स, को लाखों करोड़? माफ करके भारत और बैंको को दिवालिया रुग्ण बीमार स्टेज में पहुंचा दिया S&P इंटरनेशनल क्रेडिट रेटिंग एजेंसी रिपोर्ट 2023 में भारत की कुल GDP का रु की बर्बादी की दास्तान और दोनो मित्रो को बाजार का सारा रुपये सौंप देने की भयावह दास्तान रिपोर्ट, ने कब का चेतावनी दे दिया है भारत का खर्चा तो विदेशी बैंको से कर्जा लेकर चल रहा है, कुछ psu बिक रहे है, उससे चल रहा है भारत पर कुल बिदेशी कर्ज़ 267 लाख करोड़ रु हो गया है भूख इंडेक्स, में एशिया से सबसे नीचे छोड़िए नाइजीरिया से नीचे आ गया है भारतीय रुपया एशिया की करेंसी लिस्ट से बाहर होकर विदेश टूर, पर निकल गया है? रु. 22 करोड़ गरीबी 80 करोड़ होकर 05 किलो अनाज की लाइन में खड़ी ही हो गई है। देश का राम नाम सत्य हो गया है। अंधभक्तो-मन्दिर वाले शहर अयोध्या प्रयागराज से भी भगाया गया है, ढ़ोंगीयी को सुधर जाओ सबक ले लो... वरना पब्लिक परेशान है कुछ भी कर सकती है।

जवाहरलाल नेहरू जैसे व्यक्ति के लिए जो जनता से इतना घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ था, उसका आर्थिक दर्शन अत्यंत मानवीय, वर्तमान की जीवंत चीज और व्यावहारिक था। अंतिम विश्लेषण में, सभी आर्थिक दर्शन का केंद्रीय बिंदु और लक्ष्य गरीबी और अभाव का उन्मूलन है, और नेहरू का दर्शन भी इससे अलग नहीं था। गांधीजी ने पहले ही 'दरिद्र नारायण' के अपने प्रसिद्ध प्रतीकवाद के साथ गरीबी पर ध्यान केंद्रित किया था। नेहरू ने इस केंद्रीय समस्या पर अपने आधुनिक दिमाग और उसके वैज्ञानिक स्वभाव को लागू किया। इस प्रकार, उनके गहन मानवतावाद से प्रभावित वैज्ञानिक समाजवाद उनका बौद्धिक उपकरण बन गया। वह एक व्यावहारिक आदर्शवादी थे, और यह परस्पर विरोधाभासी नहीं है।

### फेबियन प्रभाव

अपनी युवावस्था में, नेहरू ब्रिटिश समाजवादी विचारों की ओर आकर्षित हुए, उस समय जब फेबियन सोसाइटी के बैनर तले शॉ वेल्स और वेब्स संसदीय सरकार के ढांचे के भीतर आवश्यक सेवाओं और बुनियादी उद्योगों के समाजीकरण का प्रचार कर रहे थे, जो गरीबी को खत्म करने और सभी के लिए काम सुनिश्चित करने का सबसे अच्छा साधन है। लेकिन यह वास्तव में मार्क्सवाद और रूस में कम्युनिस्ट प्रयोग का उनका अध्ययन था जिसने आर्थिक विकास और सामाजिक समानता के लिए समाजवाद की संभावनाओं में उनकी रुचि को बढ़ाया। ऐसा कहा जाता है कि कार्ल मार्क्स के अधिकांश प्रशंसकों ने उनकी 'कैपिटल' नहीं पढ़ी है, लेकिन नेहरू इस श्रेणी में नहीं थे। कुछ साल पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जब सवाल साम्यवाद पर थे, तो उन्होंने अपने श्रोताओं से पूछा कि क्या उन्होंने मार्क्सवादी क्लासिक पढ़ा है। किसी ने भी हाँ कहने की हिम्मत नहीं की, जिस पर नेहरू ने कहा कि उन्होंने इसे पढ़ा है। जब वे अपने पिता के साथ रूस गए, तो वे इस बात से प्रभावित हुए (लेकिन उनके पिता नहीं) कि रूस समाज को बदलने के लिए क्या कर रहा था। लेकिन इस अवधि के काफी पहले, वे साम्यवाद की हिंसा से भयभीत थे, हालाँकि उनका मानना था कि पूंजीवाद भी हिंसक हो सकता है। 1926 में इंग्लैंड में कोयला हड़ताल के दृश्य ने उन्हें बहुत प्रभावित किया। हालाँकि, पूंजीवाद की हिंसा एक अलग तरह की थी और इसके लिए सामाजिक उपाय भी थे। यह हिंसा नहीं बल्कि उत्पीड़न था।

### स्वतंत्रता पहले

बौद्धिक रूप से नेहरू धीरे-धीरे समाजवाद को आर्थिक विकास के बराबर मानने लगे। 1930 के दशक की महामंदी ने उन्हें यह विश्वास दिलाया कि पूंजीवाद के तहत निर्बाध आर्थिक प्रगति संभव नहीं है। उन्होंने पश्चिम में मंदी की तुलना रूस द्वारा उस समय अपनी नई-नई शुरू की गई पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से उत्पादन में की जा रही उल्लेखनीय वृद्धि से की। जबकि यह धारणा बौद्धिक स्तर पर बनी रही, जब वे भारत में कांग्रेस की राजनीति में उतरे, तो नेहरू को एक अलग स्थिति का सामना करना पड़ा, जिसके अनुसार उन्हें अपने समाजवादी विचारों को अपनाना पड़ा।

### पूंजीवाद के प्रति रवैया

भारतीय अर्थव्यवस्था का ब्रिटिश शोषण स्पष्ट था और इस पर नेहरू के विचार मोटे तौर पर दादाभाई नौरोजी, रानाडे और गोखले जैसे राष्ट्रवादी अर्थशास्त्रियों के विचारों के अनुरूप थे। लेकिन उन्होंने भारतीय पूंजीवाद का समर्थन करने या भारतीय आर्थिक विकास में इसकी भूमिका को उचित ठहराने से सावधानीपूर्वक परहेज किया। ऐसा प्रतीत होता है कि उन्होंने यह स्वीकार नहीं किया कि भारत के आर्थिक विकास के लिए पूंजीवाद आवश्यक था। वह इस प्रचलित राय के साथ खड़े थे कि राष्ट्रीय स्वतंत्रता पहला मुद्दा है और आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त करने का सबसे अच्छा तरीका बाद में तय किया जाएगा। इसके साथ ही, उन्होंने हमेशा समाजवाद में अपने विश्वास को अपने दिमाग में रखा।

आर्थिक पक्ष पर, राष्ट्रीय आंदोलन के भीतर उनका धर्मयुद्ध भूमि में सामंती संपत्ति संबंधों के खिलाफ था। उन्होंने अपने गृह प्रांत में जमींदारी प्रथा के खिलाफ एक अथक अभियान चलाया। यह विश्वास कि भारत जैसे मुख्य रूप से कृषि प्रधान देश में वास्तव में कोई समतावादी समाज नहीं हो सकता जब तक कि भूमि में सभी सामंती अवशेषों को समाप्त नहीं कर दिया जाता, उनके साथ अंत तक जीवित रहा।

### गांधीजी के विचारों को अस्वीकार करना

गांधीजी के आर्थिक विचार, अस्पष्ट रूप से मानवतावादी समाजवाद के बजाय वैज्ञानिकता से जुड़े थे, जिससे श्री नेहरू पर अधिक प्रभाव नहीं पड़ा। गांधीजी का आधुनिक उद्योग का विरोध और स्वैच्छिक गरीबी की उनकी योग्य स्वीकृति संभवतः उस व्यक्ति को पसंद नहीं आ सकती थी, जो आधुनिक उत्पादन के साधनों पर आधुनिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग द्वारा प्राप्त किए जा सकने वाले उच्च जीवन स्तर में विश्वास करता हो। उन्होंने गांधीजी के इस सिद्धांत को भी खारिज कर दिया कि अमीर लोग गरीबों के ट्रस्टी हैं। नेहरू की औपचारिक शिक्षा प्राकृतिक विज्ञानों में हुई थी। सामाजिक विज्ञान में, वे एक स्व-शिक्षित व्यक्ति थे। इस मिश्रण से वैज्ञानिक-मानवतावादी स्वभाव उत्पन्न हुआ, जो नेहरू के आर्थिक दर्शन की विशेषता थी। हाल ही में, पश्चिमी विचारों ने यह तर्क दिया है कि वैज्ञानिक और मानवतावादी संस्कृतियां विरोधी हैं। लेकिन नेहरू उनके संश्लेषण का मूर्त रूप थे

### मानवतावादी मूल्य

स्वतंत्रता से पहले नेहरू अपने आर्थिक विचारों के व्यावहारिक सूत्रीकरण के सबसे करीब 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा गठित राष्ट्रीय योजना समिति में किए गए कार्य में पहुंचे थे। उस समिति ने योजना को ऐसी चीज के रूप में परिभाषित किया था जिस पर न केवल अर्थशास्त्र और बढ़ते जीवन स्तर के दृष्टिकोण से, बल्कि सांस्कृतिक और आध्यात्मिक मूल्यों के दृष्टिकोण से भी विचार किया जाना चाहिए। उस समय उन्होंने लोकतांत्रिक विकास के लिए जो चिंता व्यक्त की थी और आर्थिक और अतिरिक्त-आर्थिक जीवन के बीच जिस अंतर-संबंध पर उन्होंने जोर दिया था, वह हमेशा उनके साथ रहा। जब वर्षों बाद उन्होंने एशिया और सुदूर पूर्व के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक आयोग को संबोधित किया, तो उन्होंने कहा कि वे कोई विशेषज्ञ नहीं थे (हालांकि विशेषज्ञ अपरिहार्य थे), लेकिन उन्हें इंसानों से निपटना पसंद था। राष्ट्रीय योजना समिति का काम अपने विचारों को लागू करने के लिए राजनीतिक शक्ति के बिना अकादमिक रहा। इसलिए यह वास्तव में 1947 में स्वतंत्रता का आगमन था जिसने नेहरू को आर्थिक भारत के अपने दृष्टिकोण को ठोस रूप देने का अवसर दिया।

### क्रमिकता की अनिवार्यता

लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत राजनीतिक सत्ता में, नेहरू ने समाजवाद और एक अविकसित देश के आर्थिक विकास के बीच संघर्ष को महसूस किया, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों न हो। वह जो हिंसा रहित साम्यवाद और समाजवाद की प्रशंसा करता था, उसने खुद को याद दिलाया कि सामाजिक पुनर्निर्माण के लिए समय का कारक भी महत्वपूर्ण है। अपने युवा दिनों में, वह आरएच टावनी की क्लासिक, 'अक्विजिटिव सोसाइटी' से प्रभावित रहा होगा, लेकिन अब उसने स्वीकार किया कि ऐसे समाज से समाजवाद और सहयोग में परिवर्तन 'अचानक कानून' द्वारा नहीं लाया जा सकता है। 1957 में इंदौर में ँध्ण सत्र में बोलते हुए, उन्होंने कहा कि रूस को खुद को औद्योगिक बनाने में 35 साल या उससे अधिक समय लगा था, और माओ त्से-तुंग ने कहा था कि चीन को 'किसी तरह का समाजवाद' हासिल करने में 20 साल लग सकते हैं। उन्होंने कहा, 'हमें यह समझना चाहिए कि भारत में समाजवाद लाने की प्रक्रिया, खासकर जिस तरह से हम इसे करने की कोशिश कर रहे हैं, यानी लोकतांत्रिक तरीके से, अनिवार्य रूप से समय लेगी। जब उन्होंने 1936 में अपनी आत्मकथा प्रकाशित की, तो समीक्षकों ने कहा कि उन्होंने क्रांति की अनिवार्यता मान ली थी। बीस साल बाद, वह क्रमिकता की अनिवार्यता को स्वीकार करने लगे थे।

### मिश्रित अर्थव्यवस्था की अवधारणा

1948 का औद्योगिक नीति प्रस्ताव भारत में समाजवाद को प्राप्त करने के लिए नेहरू के साधनों की सबसे ठोस अभिव्यक्ति थी। यहीं पर मार्क्सवादी द्वंद्ववाद के बजाय ब्रिटिश समाजवादी विचारों की उनकी बौद्धिक प्रशंसा स्पष्ट रूप से सामने आई।

प्रस्ताव में भारत के लिए 'मिश्रित अर्थव्यवस्था' की बात कही गई थी और यह अवधारणा कायम रही, भले ही बाद के वर्षों में कांग्रेस ने समाजवाद के बारे में जो कुछ भी कहा हो। जब नेहरू ने प्रस्ताव पर बात की थी, तब उन्होंने तकनीकी परिवर्तन के संदर्भ में समाजवादी अर्थव्यवस्था को समझने के महत्व को सामने रखा था। एक संक्रमणकालीन अर्थव्यवस्था में, व्यक्ति को खुद को आर्थिक प्रगति की स्थिर अवधारणा में नहीं बल्कि गतिशील में रखना चाहिए।

गतिशीलता तकनीकी परिवर्तन से आई। राज्य एक नया और तकनीकी रूप से मजबूत क्षेत्र बनाएगा, और अपने संसाधनों को ऐसे उत्पादक संसाधनों को प्राप्त करने में बर्बाद नहीं करेगा जो अप्रचलित हो सकते हैं। इस दर्शन का मतलब था उस भूमिका को पहचानना जिसे तब से निजी क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। खुद को फिर से याद दिलाते हुए कि पूंजीवादी संरचना स्वाभाविक रूप से अधिग्रहणकारी है, उन्होंने एक सहकारी क्षेत्र के मूल्य का प्रचार करना शुरू किया जो पूंजीवाद के असामाजिक पक्ष का मुकाबला करने में मदद करेगा। ऐसा कहा जाता है कि बाद के वर्षों में नेहरू 'प्रबुद्ध पूंजीवाद' की प्रशंसा करने लगे और निजी तौर पर उन्होंने एक प्रमुख भारतीय व्यापारिक घराने की भी प्रशंसा की।

### योजना आयोग

योजना आयोग की स्थापना और इसके द्वारा शुरू किए गए नियोजन युग ने नेहरू को आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए एक

साथ काम करने का मौका दिया। हाल के वर्षों में भारतीय नियोजन की विफलता पर उन्होंने जो निराशा व्यक्त की, वह इन उद्देश्यों को प्राप्त करने में उनकी आस्था का एक पैमाना था। गरीबी के खिलाफ उनके उग्र क्रोध ने नियोजन प्रक्रिया की गलत गणनाओं पर उनकी निराशा को और बढ़ा दिया। पारंपरिक अर्थों में अर्थशास्त्री न होने के कारण, वह अर्थव्यवस्था में बार-बार होने वाली टूट-फूट को समझ नहीं पाए।

उन्होंने भूमि सुधारों, प्रौद्योगिकी के प्रयोग के माध्यम से उत्पादन बढ़ाने तथा पूंजीवाद के भीतर वितरणात्मक न्याय सुनिश्चित करने के लिए सहयोग फैलाने के महत्व पर जोर देना जारी रखा। वास्तव में ये लगभग 15 वर्षों तक भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ को दिए गए उनके वार्षिक संबोधनों के विषय थे । परमाणु ऊर्जा में उनकी गहरी रुचि उनकी वैज्ञानिक सोच का नवीनतम उदाहरण थी।

## दर्शनशास्त्र विश्वविद्यालय

नेहरू को अंतरराष्ट्रीय आर्थिक सहयोग पर अपने विचार व्यक्त करने के बहुत ज़्यादा अवसर नहीं मिले। लेकिन जब उन्हें ऐसा करने का मौक़ा मिला - जैसे कि जब उन्होंने ECAFE या कोलंबो योजना की बैठकों या संयुक्त राष्ट्र में भाषण दिया - तो उन्होंने अपने विचारों में वही सार्वभौमिकता प्रतिबिंबित की जो उनके राजनीतिक दर्शन का मूलमंत्र था। यूरोपीय आर्थिक समुदाय जैसे आर्थिक ब्लॉकों के विरोध में भी, उनका आर्थिक दर्शन उनके राजनीतिक दर्शन के साथ पूरी तरह से सुसंगत था। यह आपसी मदद, भय और घृणा की अनुपस्थिति और अच्छे पड़ोसी पर आधारित था। उन्हें युरिपीडीज़ की ये पंक्तियाँ बहुत पसंद थीं, जिन्हें उन्होंने कम से कम दो मौकों पर उद्धृत किया। वे उनके दर्शन का सार प्रस्तुत करती हैं।

'और क्या बुद्धिमत्ता है? मनुष्य के प्रयास या ईश्वर की उच्च कृपा, जो इतनी प्यारी और इतनी महान है? भय से मुक्त होकर सांस लेना और प्रतीक्षा करना, घृणा के ऊपर हाथ उठाना, और क्या सुंदरता को हमेशा के लिए प्यार नहीं किया जाएगा?'

## क्रमिकता की अनिवार्यता

लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत राजनीतिक सत्ता में, नेहरू ने समाजवाद और एक अविकसित देश के आर्थिक विकास के बीच संघर्ष को महसूस किया, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों न हो। वह जो हिंसा रहित साम्यवाद और समाजवाद की प्रशंसा करता था, उसने खुद को याद दिलाया कि सामाजिक पुनर्निर्माण के लिए समय का कारक भी महत्वपूर्ण है। अपने युवा दिनों में, वह आरएच टावनी की क्लासिक, 'अक्विजिटिव सोसाइटी' से प्रभावित रहा होगा, लेकिन अब उसने स्वीकार किया कि ऐसे समाज से समाजवाद और सहयोग में परिवर्तन 'अचानक कानून' द्वारा नहीं लाया जा सकता है।

1957 में इंदौर में AICC सत्र में बोलते हुए, उन्होंने कहा कि रूस को खुद को औद्योगिक बनाने में 35 साल या उससे अधिक समय

लगा था, और माओ त्से-तुंग ने कहा था कि चीन को 'किसी तरह का समाजवाद' हासिल करने में 20 साल लग सकते हैं। उन्होंने कहा, 'हमें यह समझना चाहिए कि भारत में समाजवाद लाने की प्रक्रिया, खासकर जिस तरह से हम इसे करने की कोशिश कर रहे हैं, यानी लोकतांत्रिक तरीके से, अनिवार्य रूप से समय लेगी। जब उन्होंने 1936 में अपनी आत्मकथा प्रकाशित की, तो समीक्षकों ने कहा कि उन्होंने क्रांति की अनिवार्यता मान ली थी। बीस साल बाद, वह क्रमिकता की अनिवार्यता को स्वीकार करने लगे थे।

## मिश्रित अर्थव्यवस्था की अवधारणा

1948 का औद्योगिक नीति प्रस्ताव भारत में समाजवाद को प्राप्त करने के लिए नेहरू के साधनों की सबसे ठोस अभिव्यक्ति थी। यहीं पर मार्क्सवादी द्वंद्ववाद के बजाय ब्रिटिश समाजवादी विचारों की उनकी बौद्धिक प्रशंसा स्पष्ट रूप से सामने आई।

प्रस्ताव में भारत के लिए 'मिश्रित अर्थव्यवस्था' की बात कही गई थी और यह अवधारणा कायम रही, भले ही बाद के वर्षों में कांग्रेस ने समाजवाद के बारे में जो कुछ भी कहा हो। जब नेहरू ने प्रस्ताव पर बात की थी, तब उन्होंने तकनीकी परिवर्तन के संदर्भ में समाजवादी अर्थव्यवस्था को समझने के महत्व को सामने रखा था। एक संक्रमणकालीन अर्थव्यवस्था में, व्यक्ति को खुद को आर्थिक प्रगति की स्थिर अवधारणा में नहीं बल्कि गतिशील में रखना चाहिए। गतिशीलता तकनीकी परिवर्तन से आई। राज्य एक नया और तकनीकी रूप से मजबूत क्षेत्र बनाएगा, और अपने संसाधनों को ऐसे उत्पादक संसाधनों को प्राप्त करने में बर्बाद नहीं करेगा जो अप्रचलित हो सकते हैं। इस दर्शन का मतलब था उस भूमिका को पहचानना जिसे तब से निजी क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। खुद को फिर से याद दिलाते हुए कि पूंजीवादी संरचना स्वाभाविक रूप से अधिग्रहणकारी है, उन्होंने एक सहकारी क्षेत्र के मूल्य का प्रचार करना शुरू किया जो पूंजीवाद के असामाजिक पक्ष का मुकाबला करने में मदद करेगा। ऐसा कहा जाता है कि बाद के वर्षों में नेहरू 'प्रबुद्ध पूंजीवाद' की प्रशंसा करने लगे और निजी तौर पर उन्होंने एक प्रमुख भारतीय व्यापारिक घराने की भी प्रशंसा की।

## योजना आयोग

योजना आयोग की स्थापना और इसके द्वारा शुरू किए गए नियोजन युग ने नेहरू को आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए एक साथ काम करने का मौका दिया। हाल के वर्षों में भारतीय नियोजन की विफलता पर उन्होंने जो निराशा व्यक्त की, वह इन उद्देश्यों को प्राप्त करने में उनकी आस्था का एक पैमाना था। गरीबी के खिलाफ उनके उग्र क्रोध ने नियोजन प्रक्रिया की गलत गणनाओं पर उनकी निराशा को और बढ़ा दिया। पारंपरिक अर्थों में अर्थशास्त्री न होने के कारण, वह अर्थव्यवस्था में बार-बार होने वाली टूट-फूट को समझ नहीं पाए।

उन्होंने भूमि सुधारों, प्रौद्योगिकी के प्रयोग के माध्यम से उत्पादन बढ़ाने तथा पूंजीवाद के भीतर वितरणात्मक न्याय सुनिश्चित करने के लिए सहयोग फैलाने के महत्व पर जोर देना जारी रखा। वास्तव में ये लगभग 15 वर्षों तक भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ को दिए गए उनके वार्षिक संबोधनों के विषय थे । परमाणु ऊर्जा में उनकी गहरी रुचि उनकी वैज्ञानिक सोच का नवीनतम उदाहरण थी।

## दर्शनशास्त्र विश्वविद्यालय

नेहरू को अंतरराष्ट्रीय आर्थिक सहयोग पर अपने विचार व्यक्त करने के बहुत ज़्यादा अवसर नहीं मिले। लेकिन जब उन्हें ऐसा करने का मौक़ा मिला - जैसे कि जब उन्होंने ECAFE या कोलंबो योजना की बैठकों या संयुक्त राष्ट्र में भाषण दिया - तो उन्होंने अपने विचारों में वही सार्वभौमिकता प्रतिबिंबित की जो उनके राजनीतिक दर्शन का मूलमंत्र था। यूरोपीय आर्थिक समुदाय जैसे आर्थिक ब्लॉकों के विरोध में भी, उनका आर्थिक दर्शन उनके राजनीतिक दर्शन के साथ पूरी तरह से सुसंगत था। यह आपसी मदद, भय और घृणा की अनुपस्थिति और अच्छे पड़ोसी पर आधारित था। उन्हें युरिपीडीज़ की ये पंक्तियाँ बहुत पसंद थीं, जिन्हें उन्होंने कम से कम दो मौकों पर उद्धृत किया। वे उनके दर्शन का सार प्रस्तुत करती हैं।

'और क्या बुद्धिमत्ता है? मनुष्य के प्रयास या ईश्वर की उच्च कृपा, जो इतनी प्यारी और इतनी महान है? भय से मुक्त होकर सांस लेना और प्रतीक्षा करना, घृणा के ऊपर हाथ उठाना, और क्या सुंदरता को हमेशा के लिए प्यार नहीं किया जाएगा?'

# अधिकांश कार्य एवं उत्पादन कागजों पर, धन बंदर बांट में हजम

**पेज 3 का शेष**

जिसमें कृषकों को केंद्र की निम्न योजनाओं में अनुदान दिया जाता है। हर बूंद ज्यादा फसल, एकीकृत बागवानी विकास मिशन, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, और राष्ट्रीय औषधि पौध मिशन, मौसम आधारित फसल बीमा योजना, आत्मनिर्भर भारत की योजनाएं, राज्य सरकार की योजनाओं में फल क्षेत्र विस्तार, मसाला क्षेत्र विस्तार, सब्जी क्षेत्र विस्तार, संरक्षित खेती, उद्यानकी के विकास हेतु यंत्रीकरण को बढ़ावा देने की योजना, घरेलू बागवानी की आदर्श किचन गार्डन योजना, औषधि एवं सुगंधित फसल क्षेत्र विस्तार, कृषक प्रशिक्षण तथा भ्रमण कार्यक्रम, प्रदर्शनी मेला प्रचार प्रसार योजना मुख्यमंत्री बागवानीव खाद्य प्रसंस्करण योजना आदि योजनाओं में हर योजना में किसानों के लिए अनुदान की व्यवस्था की जाती है पर इन अनुदानों के नाम पर यहां बैठे उपसंचालक सहायक संचालक से लेकर ग्रामीण उद्यानिकी विकास अधिकारी तक अनुदान के नाम पर भारी वसूली करते हैं। वर्तमान में इंदौर संभाग में ही अधिकांश वरिष्ठ उद्यान विकास तृतीय श्रेणी अधिकारी जिनका वेतनमान 9300-34800 है अधिकांश सहायक संचालक जिनका वेतनमान रु15600 से 39100 होता है। के पदों पर मोटा प्रभार देकर बैठे हुए हैं।

इंदौर में ही पिछले 5 साल से घोर भ्रष्ट मक्कार संयुक्त संचालक दयाराम जाटव प्रभार में बैठा हुआ है, जिसे शीघ्र स्थानांतरण किया जाना चाहिए इंदौर के उद्यानिकी प्रशिक्षण केंद्र में सहायक संचालक धारीवाल इंदौर में प्रभारी उपसंचालक धूम सिंह चौहान, धार में उपसंचालक प्रभारी मोहन सिंह मुजाल्दा, झाबुआ में प्रभारी सहायक संचालक उद्यान नीरज सांवलिया, अलीराजपुर में कैलाश चौहान प्रभारी सहायक संचालक उद्यान, खरगोन में प्रभारी के के गिरवाल उपसंचालक बड़वानी में भी कैलाश चौहान के पास ही प्रभार है। खंडवा में अजय चौहान उपसंचालक प्रभारी रीछी फार्म हाउस खंडवा में प्रभारी सहायक संचालक बहादुर सिंह चौहान और बुरहानपुर में प्रभारी उपसंचालक उद्यान राजू बड़वाह बैठा हुआ है। उज्जैन में प्रभारी संयुक्त संचालक आशीष कनेश इसे भी काफी लंबा समय गुजर गया है शीघ्र स्थानांतरण किया जाना

चाहिए। उज्जैन जिला प्रभारी उपसंचालक पप्पू सिंह कनेर शाजापुर में मनीष सिंह चौहान उप संचालक प्रभारी आगर मालवा में प्रभारी उपसंचालक सुरेश राठौड़, देवास में प्रभारी उपसंचालक पंकज शर्मा, रतलाम में प्रभारी त्रिलोक वास्केले, मंदसौर में कैलाश सिंह सोलंकी प्रभारी, नीमच में प्रभारी अंतर सिंह कन्नौजी उपसंचालक, कन्नौद फार्म हाउस में जय सिंह सेनानी प्रभारी उप संचालक पदस्थापनाओं पर सभी प्रभारी भारी भ्रष्टाचार कर रहे हैं। सूचना के अधिकार में जब उनसे जानकारी मांगी जाती है तो जानकारी देने के नाम पर कोई भी यूआरएल और सीडी नहीं दी जाती और फिर इनका वरिष्ठ अधिकारियों को शिकायत करने पर हरामखोर सचिवालय से लेकर मुख्यालय वह संयुक्त संचालक कार्यालय तक हरि शिकतों के ऊपर सुनवाई करने की अपेक्षावसूली करके बंद करके रख दी जाती है। फिर हजारों में शुल्क मांगा जाता है। यहां पर भी अधिकांश योजनाओं में इसमें खास तौर से फल क्षेत्र विस्तार मसाला क्षेत्र विस्तार सभी क्षेत्र विस्तार संरक्षित खेती घरेलू बागवानी औषधि एवं संरक्षित फसल क्षेत्र आदि में सारा पैसा कागजों पर दिखाकर हजम कर लिया जाता है। पूर्व में भी सांवलिया देवास ने जो भ्रष्टाचार किए थे और अभी वहीं भ्रष्टाचार पंकज शर्मा भी दोनों हाथ से बटोरकर कर रहा है। यथार्थ में पूरे उद्यान की विभाग में पूरे प्रदेश में राज्य शासन की ओर केंद्र शासन की योजनाओं का पैसा सारे के सारे प्रभारी जो मोटा प्रभार देते हैं हर महीने आधे से ज्यादा हजम कर जाते हैं। कृषकों को सेडनेट हाउस ग्रीन हाउस स्प्रिंकलर आदि के यंत्रीकरण के लिए दिए जाने वाले पाइप लाइन का स्प्रिंकलर आदि के धन का अधिकांश पैसा हजम कर लिया गया। इंदौर, देवास व प्रदेश के अन्य जिलों में कृषकों को यंत्रीकरण, व अन्य योजनाओं के नाम पर भी हुए भ्रष्टाचार में अनेकों बार जांच भी बैठी और निष्कर्ष में सारी लीपा पोती करके सबको बचा लिया गया। क्योंकि सारे हरामखोर भ्रष्टों ने नीचे से ऊपर तक सब ने मिल बांट कर खाया था। इसलिएसाड़ी फाइनल दबा दी गई दूसरी तरफ संचालक के रूप में इस विभाग को पिछले 15-20 सालों से लगातार कभी भारतीय प्रताड़ना सेवा अधिकारी कभी वन लूटो खाओं सेवा अधिकारी के रूप में संचालकसदस्य किए जाते हैं जिनका उद्देश्य विभाग विभाग की योजनाएं प्रदेश के कृषकों के साथ सभी प्रकार की औषधि मसाला फलों आदि के उत्पादन की ओर ध्यान देने की अपेक्षा सबका ध्यान केवल कागजी आंखों को भरकर मोटी कमाई करना होता है आखिर यह भ्रष्ट मंत्रालय सूचना के अधिकार की धारा 4 के अंतर्गत सभी 25 बिंदुओं की जानकारीअपनी साइट पर अपलोड क्यों नहीं करता जिस प्रकार से ग्रामीण विकास विभाग के हर खरीदी बिक्री की वाउचर की जानकारी तकसाइट पर अपलोड होती है कितना आवंटन कितना अनुदान किस दशक को किस योजना में दिया गया उसकी भौतिक जानकारी उपलब्ध करवाई जानी चाहिए अधिकांश स्टाफ यहां का घोर निठल्ला होने के साथ सबकी निगाहें केवल भ्रष्टाचार से धन भजन करने पर लगी रहती हैं जबकि जितना बजट आता है उसका आधा भी सही ढंग से उद्यानिकी फसलों के विकास में खर्च किया जाए। तो न केवल प्रदेश के किसान बल्कि प्रदेश सरकार भी औषधियों मसालों फलों की ऊपजों से काफी राजस्व प्राप्त कर सकता है।

साप्ताहिक समय माया

## 14 साल से लिख रहा हूं, इवीएम पूरी जालसाजी

# इवीएम कलेक्टर, चुनाव आयोग से आम तक परिणाम बदलने में सक्षम

## मुंबई में मोबाइल से परिणाम बदले

**लोकसभा चुनावः एनडीए कैंडिडेट के रिश्तेदार का फोन शिंदे सेना सांसद के रिश्तेदार पर मतगणना केंद्र में फोन ले जाने का मामला दर्ज, रिपोर्ट में कहा गया 'ईवीएम से जुड़ा'**

विश्व के वैद्युतकीय संचार क्रांति के अग्रिम पंक्ति के देशों यथा अमेरिका चीन ब्रिटेन फ्रांस रूस जापान आदि मैं भी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन काप्रयोग नहीं किया जाता है पर भारत में सत्ताधीश भाजपा को समझ में आ चुका है, कि सत्ता में बैठने के लिए इबीएम की जालसाजी सबसे सरल सटीक तरीका है जहां से ईवीएम मशीन को जिसमें मदरबोर्ड लगा होने के साथ सॉफ्टवेयर से कमांड दे, मतदान की संख्या को घटाने बढ़ाने से लेकर कलेक्टर चुनाव आयोग से लेकर आम आदमी भी मोबाइल से परिणाम बदलकर भी मन चाहे परिणाम प्राप्त किये जा सकते हैं। 2024 के चुनाव में मशीनों को बदलने से लेकर इसके संबंध में आपको बता दें की इवीएम चुनाव आयोग की संपत्ति नहीं है वह किराए पर ली जाती है टेंडर पर भी ली जाती है और जिस भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन लिमिटेडनेस को बनाया उसने जहां पूरे देश में आपूर्ति की थी बीच में ही 15 लाख मशीन गायब हो गई थी जिसकी आज तक चोरी गायब होने की कोई प्रथम सूचनारिपोर्ट भी देश के किसी थाने में नहीं की गई और उनका खुलकर दुरुपयोग होता रहा है। जो मतदान की बात बदलने से लेकरस्ट्रांग रूम में बदलने के साथगिनती के समयजिसमें मतदान हुआ है वह मशीन हटा दी जाती है और पूर्व से भरी हुई मशीन लाकर रख दी जाती है। जिसके सैकड़ों वीडियो सामने आए। मनचाहे परिणाम लेने के लिए जीपीएस जीपीआर एस डब्ल्यूएलएल, वाई-फाई से नियंत्रित होने के साथमतदान के बादकेवल ऊपरी हिस्से पर सील लगाई जाती है जबकि उसके सारे पोर्ट खुले होते हैं। जिसे आसानी से कनेक्ट कर मनचाहे परिणाम लिए जा सकते हैं। इसके संबंध नहीं एक घटना 18 अप्रैल 2014 को शाम 4:30 बजे इंदौर की कलेक्टर ऑफिस से फोन आया जिसमें संबंधित व्यक्ति ने मुझसे कहा आप लोकसभा प्रत्याशी हैं अजमेरा सर मशीन लॉक कर रहे हैं आप आ जाइए। तो मैंने उसे कहा भाई मैंने एक मोबाइल ढाई इंच भाई 5 इंच का रु. 10000 में मुश्किल से पैसे इकट्ठे कर खरीदा था। 3 साल से सीने से लगाकर घूमने के बाद में भी आज तक मुझे उसके पूरे फंक्शन नहीं मालूम। तो आपकी डेढ़ फुट बाय 6 इंच की मशीन मैं क्या-क्या लगा है? जीपीएस, जीपीआरएस, डबल्युएलएल, वाई-फाई, ब्लूटूथ मैं कैसे देखूंगा और समझूंगा? इंदौरी नेता जनवरी 14 सेबोल रहे हैं ताई 2 लाख वोट से जीतेगी मुझे मालूम है चार लाख से जीतने वाली है क्योंकि मशीनों में पूरी है फिर करके आप उसे चार लाख वोट से जिताओगे। मुझे तो हारना है। तो जो आपने करना है वह आपने ही पूरा करना है। उसमें मैंने कुछ नहीं कर पाना है। तो जो आपको जैसे लगे, कर लोमेरे वहां पहुंचने का कोई औचित्य नहीं।

सच तो यह है कि विपक्ष पूरी तरीके से कमजोर नामर्दों की फौज का नाम बन चुका है।

अन्यथा तो बीजेपी सही मायने में अगर ईमानदारी से गिनती भी हो जाती, तो भी पूरे देश में 40 सीट भी नहीं जीत सकती थी। मोदी ने जो फुलझड़ी छोड़ी थी। उसके पीछे उसे लग चुका था नहीं होगी 40 भी पार। पर जानबूझकर यह नारा दिया, इसीलिये दिया कि अबकी बार, 400पार क्योंकि उसने इवीएम के सभी तरह से जालसाजी के साथ गिनती में भी जालसाजी के खेल को विधानसभा चुनावों में जिसमें विशेष रूप से गुजरात के खेल में पूरी हारी हुई बड़ी पलटा कर फिर से गुजरात में कब्जा कर लिया था।

हाल ही में महाराष्ट्र में पकड़े गए ईवीएम के मोबाइल फोन से कनेक्शन से हारी सीट पर जीतने का खेल पकड़ा गया।

मुंबई उत्तर-पश्चिम सीट के लिए दोनों शिवसेना के बीच कांटे की टक्कर में एक नया मोड़ आ गया है, जहां एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली पार्टी के रवींद्र वायकर ने अंततः 48 वोटों से जीत हासिल की।

मुंबई पुलिस ने वायकर के एक रिश्तेदार पर मतगणना केंद्र के अंदर मोबाइल फोन ले जाने का आरोप लगाया है। मिड-डे की रविवार की रिपोर्ट में बताया गया है कि मंगेश पंडिलकर - वायकर के रिश्तेदार, जिनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है - जिस मोबाइल फोन का इस्तेमाल कर रहे थे, वह इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) से जुड़ा हुआ था। हालांकि, मामले से परिचित एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने दिप्रिंट को बताया: 'यह खबर सच नहीं है। एफआईआर बुधवार को केवल धारा 188 (लोक सेवक द्वारा वैधानिक रूप से प्रख्यापित आदेश की अवज्ञा) के तहत दर्ज की गई थी।'

वायकर ने रविवार को मीडियाकर्मियों से कहा, 'ठाकरे गुट अपनी हार को पचा नहीं पा रहा है। इससे उन्हें दुख पहुंचा है और इसीलिए वे शोर मचा रहे हैं। मैं उन पर कोई ध्यान नहीं देता।'

उन्होंने कहाः 'जहां तक ईवीएम हैक करने की बात है, वहां बहुत से लोग मोबाइल फोन लेकर आए थे। इसलिए धारा 188 के तहत जो भी जुर्माना है, वह लगाया जा सकता है। आप मुझे बताइए, क्या ईवीएम को इस तरह से हैक किया जा सकता है? इसलिए मैं इस पर कोई स्पष्टीकरण नहीं देना चाहता।'

शिवसेना (एकनाथ शिंदे) नेता संजय निरुपम ने दिप्रिंट से कहाः 'अगर ईवीएम हैक की गई होती तो वायकर इतने कम अंतर से नहीं जीत पाते। विपक्ष इस मुद्दे पर खूब शोर मचा रहा है। शिवसेना (यूबीटी) कह रही है कि वायकर की जीत के लिए प्रशासन जिम्मेदार है। दोनों उम्मीदवारों के पास दो बार पुनर्मतगणना की मांग करने का विकल्प था और दोनों ने इसका इस्तेमाल किया।'

उन्होंने कहाः 'अगर एमवीए उम्मीदवार ने जब पुनर्मतगणना की मांग की थी, तब उसे पुनर्मतगणना नहीं मिली होती, तो आप कह सकते थे कि प्रशासन पक्षपाती था, लेकिन ऐसा नहीं है। बाकी यह जांच का विषय है कि वह फोन किसका है, फोन की अनुमति क्यों दी गई। इसकी जांच चल रही है।'

मिड-डे की रिपोर्ट को शेयर करते हुए शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) के पूर्व मंत्री और विधायक आदित्य ठाकरे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में कहाः 'एक बार गद्दार, हमेशा गद्दार। उत्तर पश्चिम मुंबई से मिंडे गैंग के उम्मीदवार का मामला और भी उलझ गया है क्योंकि गद्दार (गद्दार) उम्मीदवार अब लोकतंत्र के साथ विश्वासघात कर रहा है।'

शिवसेना (यूबीटी) मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को 'मिन्डे' कहकर चिढ़ाती रही है - मराठी शब्द 'मिन्डा' का अर्थ है, जो दायित्वों से दबा हुआ है - अप्रत्यक्ष रूप से आरोप लगाती रही है कि शिंदे गुट भाजपा के नियंत्रण में है।

वाईकर, जिन्हें कभी उद्धव ठाकरे का करीबी माना जाता था, शिंदे की बगावत के बाद भी शिवसेना (यूबीटी) के साथ बने रहे। हालांकि, मार्च में वे शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना में शामिल हो गए । जोगेश्वरी विधायक मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की जांच के घेरे में थे, शहर में एक आलीशान होटल के प्रस्तावित निर्माण के सिलसिले में, जिसे बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) ने एक बगीचे के लिए आरक्षित किया था।

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी मिड-डे की रिपोर्ट साझा करते हुए कहा कि इससे 'हमारी चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता को लेकर गंभीर चिंताएं' पैदा होती हैं।

**'वायकर के रिश्तेदारों ने मतगणना केंद्र में फोन का इस्तेमाल किया':** हिंदू समाज पार्टी के उम्मीदवार के रूप में मुंबई उत्तर पश्चिम से चुनाव लड़ने वाले भरत शाह ने दिप्रिंट को बताया कि वायकर के रिश्तेदार मोबाइल फोन के साथ मतगणना केंद्र के अंदर थे और 4 जून को लगातार वायकर से संपर्क कर रहे थे।

चुनाव आयोग के नियमों के अनुसार, मतगणना केन्द्रों के अंदर इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की अनुमति नहीं है। शाह ने कहा, 'दोपहर 3 बजे से ही वायकर के रिश्तेदार लगातार मतगणना केंद्र के भीतर से उनसे संपर्क में थे। हमने मंगेश पंडिलकर को रंगे हाथों पकड़ा और मामले को रिटर्निंग ऑफिसर के पास ले गए।

उन्होंने हमें पुलिस के पास जाने को कहा। हमने शिकायत दर्ज कराई, लेकिन पुलिस ने हमारी शिकायत के आधार पर एफआईआर दर्ज नहीं की। उन्होंने बहुत बाद में एफआईआर दर्ज की और शिकायतकर्ता के तौर पर तहसीलदार और हमें गवाह बनाया।'

वाईकर ने शिवसेना (यूबीटी) के अमोल कीर्तिकर को हराया था। मुकाबला कांटे का था। एक समय तो ऐसा लगा कि कीर्तिकर एक वोट से जीतने की कगार पर हैं। शिवसेना (यूबीटी) के सूत्रों का कहना है कि शिंदे की अगुआई वाली शिवसेना ने पोस्टल बैलेट वोटों की दोबारा गिनती की मांग की, जिसके चलते वाईकर 48 वोटों से जीत गए। **( शेष पेज 2 पर )**

साप्ताहिक
समय माया
samaymaya.com

करोड़ों किसानों मजदूरों छोटे व्यवसायियों
उद्योगों, सरकारी कर्मचारियों अधिकारियों
ठेका संविदा कर्मियों के हितों की रक्षा व देशी
विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपनियों के षड्यंत्रों के
विरुद्ध पिछले 25 वर्षों से संघर्षरत

साप्ताहिक समयमाया समाचार पत्र व
samaymaya.com की वेबसाइट पर
समाचार, शिकायतें और विज्ञापन
( प्रिंट एवं वीडियो ) के लिए संपर्क करें

मप्र के समस्त जिलों में एजेंसी देना है
एवं संवाददाता नियुक्त करना है

मो. 9425125569 / 9479535569

ईमेल: samaymaya@gmail.com
samaymaya@rediff.com

स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक- अजमेरा एस.पी. कुमार द्वारा अपनी दुनिया प्रिंटर्स, 13 प्रेस कॉम्प्लेक्स, ए.बी. रोड, इंदौर से मुद्रित एवं 299, अम्बेडकर नगर, इंदौर (म.प्र.) से प्रकाशित।
संपादकः अजमेरा एस.पी. कुमार, मो. 9425125569, भोपाल प्रतिनिधि- एस.के. भारद्वाज मो. 9425637958